घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 278- शनिवार 08- अगस्त 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला...अब 3 घंटे के भीतर हटाना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर बढ़ते फर्जी एवं आपत्तिजनक कंटेंट पर लगाम कसने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार,अब सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी गैर-कानूनी, आपत्तिजनक या संवेदनशील सामग्री की सूचना मिलने के सिर्फ 3 घंटे के भीतर उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। पहले ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई के लिए कंपनियों को 24 से 36 घंटे तक का समय मिलता था, लेकिन अब इस समयसीमा को घटाकर तीन घंटे कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि डिजिटल युग में कोई भी डीपफेक वीडियो, एआई से तैयार की गई भ्रामक सामग्री या फर्जी खबरें कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं। इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर नुकसान हो सकता है। ऐसे में त्वरित कार्रवाई जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म निर्धारित 3 घंटे की समयसीमा का पालन नहीं करता है, तो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत मिलने वाला 'सेफ हार्बर' संरक्षण नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में संबंधित कंपनी को मध्यस्थ का कानूनी संरक्षण खोना पड़ सकता है और उसके खिलाफ सीधे कानूनी एवं आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का मानना है कि नए नियमों से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जवाबदेही बढ़ेगी, फर्जी और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर तेजी से रोक लगेगी तथा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन माहौल अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

मार्क जुकरबर्ग को तगड़ा झटका,मेटा पर ठोका गया 5,390 करोड़ का जुर्माना

न्यू मैक्सिको,07 अगस्त 2026 । सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भारत में एल्गोरिद्म और कानूनी पचड़ों में फंसी मार्क जुकरबर्ग की कंपनी को अब अमेरिका में एक बहुत बड़ा कानूनी झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के गंभीर आरोप में मेटा पर 567 मिलियन डॉलर (करीब 5,390 करोड़ रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स युवाओं को बुरी लत लगा रही हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर कंपनी की नीतियां जिम्मेदार हैं। इस फैसले के बाद मेटा को अपने प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके में भी बड़े बदलाव करने होंगे। न्यू मैक्सिको के सांता फे में हुई मामले की सुनवाई के दौरान जज ब्रायन बीडशाइड ने डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि मेटा ने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि युवा यूजर्स इसके आदी हो जाते हैं, जिससे समाज में 'पब्लिक न्यूसेंस' (सार्वजनिक परेशानी) की स्थिति पैदा हो गई है। कंपनी पर यह भी आरोप साबित हुआ है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर बच्चों को यौन शोषण जैसी गंभीर घटनाओं से बचाने में पूरी तरह से विफल रही है। यह ऐतिहासिक फैसला मामले की शुरुआत में न्यू मैक्सिको की जूरी द्वारा मेटा को 375 मिलियन डॉलर का भुगतान करने के आदेश के ठीक पांच महीने बाद आया है। जूरी ने अपनी विस्तृत जांच में पाया था कि कंपनी ने युवा यूजर्स के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम की सुरक्षा को लेकर झूठे दावे किए और गलत जानकारी फैलाई। इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून का सीधा और खुला उल्लंघन माना गया, जिसके चलते कंपनी पर यह भारी जुर्माना लगाया गया है।

हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ

9 से 17 अगस्त तक चलेगा राष्ट्रव्यापी आयोजन

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी 'हर घर तिरंगा 2026' अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक पूरे देश में आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नागरिकों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने तथा देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का आह्वान किया गया है। प्रेस वार्ता में शेखावत ने कहा कि वर्ष 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किया गया 'हर घर तिरंगा' अभियान अब एक वार्षिक राष्ट्रीय परंपरा बन चुका है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करोड़ों नागरिक स्वेच्छा से अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव का प्रदर्शन करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अभियान अब केवल ध्वजारोहण तक सीमित नहीं है, बल्कि सामुदायिक भागीदारी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरासत संरक्षण संबंधी गतिविधियों और डिजिटल सहभागिता के माध्यम से एक व्यापक जनआंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि देशभर में इसे उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। शेखावत ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि भारत की एकता, गौरव और सामूहिक राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है।

प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम को मंजूरी 8 अगस्त को होगा छात्रों की गूंज आयोजन

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पिछले कुछ दिनों से बनी अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है। कायस्थ पाठशाला (केपी) ट्रस्ट प्रबंधन ने 8 अगस्त को आयोजित होने वाले 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए केपी कॉलेज मैदान के उपयोग की अनुमति दोबारा जारी कर दी है। इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों और कार्यक्रम से जुड़े आयोजकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। केपी ट्रस्ट प्रबंधन की ओर से जारी नए अनुमति पत्र के बाद कार्यक्रम स्थल को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया के सामने ट्रस्ट द्वारा जारी आधिकारिक पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि अब कार्यक्रम निर्धारित तिथि और स्थान पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और आयोजन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गौरतलब है कि इससे पहले 5 अगस्त को केपी ट्रस्ट प्रबंधन ने कुछ तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए मैदान के उपयोग की अनुमति निरस्त कर दी थी।

संसद में विपक्ष का प्रदर्शन...दोनों सदन सोमवार तक स्थगित

लोकसभा से एमएसएमई संशोधन बिल पास

कांग्रेस का सभी सांसदों को सदन में रहने का निर्देश

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को भी संसद परिसर में तेज बारिश के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर-मंतर प्रदर्शन में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं, विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) एमएसएमई विधेयक 2026 ध्वनिमत से पास हुआ। दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने 'अमित शाह सदन में आओ' के नारे लगाए। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शाह सुबह से रात तक संसद में ही रहते हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा कि अमित शाह का नाम सुनते ही आतंकी कांप उठते हैं। इसी बीच कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक संसद में मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर चर्चा की

मांग की है। सांसद मणिकम टैगोर ने गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मामले पर बयान देने और न्यायिक जांच कराने की मांग की। लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार को 11 बजे शुरू हुई लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई। 12 बजे दोबारा कार्यवाही शुरू हुई और 10 मिनट तक चली लेकिन फिर सोमवार तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई और 30 मिनट तक चली। लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण पहले 12 बजे तक और फिर 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक 2026 (एमएसएमई विधेयक) ध्वनिमत से पास हुआ। इसके बाद लोकसभा सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किया, 10 से 12 अगस्त तक सदन में रहने के निर्देश

कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा के अपने सभी सांसदों को 10,11 और 12 अगस्त को सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। पार्टी ने कहा है कि इन दिनों संसद में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, इसलिए सभी सांसदों की उपस्थिति जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक,कांग्रेस ने INDIA गठबंधन के सहयोगी दलों से भी अपने सांसदों की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा है। माना जा रहा है कि अगले सप्ताह संसद में एफसीआरए संशोधन विधेयक और परिसीमन से जुड़े अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

सीमा पार आतंकवाद खत्म होने पर ही पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध संभव : सरकार

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। केन्द्र सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में कहा कि पाकिस्तान के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध तभी संभव हैं,जब वह सीमा पार आतंकवाद,शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल सुनिश्चित करे। सरकार ने स्पष्ट किया कि सीमा पार आतंकवाद और उससे जुड़ा ढांचा समाप्त करना भारत की स्पष्ट और अटल नीति है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि, पाकिस्तान से प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद अब भी जारी है और आतंकवाद का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध आधिकारिक नीति के रूप में किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा वापस ले लिया था तथा पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया गया था।

झारखंड प्रदर्शन...एआईएसए अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंकी

आरोपी को हिरासत में लिया गया

रांची,07 अगस्त 2026। झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की परीक्षा रद्द करने तथा जेपीएससी-जेएसएससी भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन शुक्रवार को 14वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन को समर्थन देने के लिए अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए निकले। इस दौरान आइसा की प्रदेश अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवक ने स्याही फेंक दी। पुलिस ने आरोपी युवक को तत्काल हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़ा हुआ है। इधर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे छात्र राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी सुधार मंच के विनय मेहता ने

बताया कि राहुल पिछले चार दिनों से केवल पानी के सहारे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। शुक्रवार सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई,जिसके बाद उन्हें अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया,जहां उनका उपचार जारी है। स्याही फेंकने की घटना के बाद नेहा बोरा ने कहा कि वह इस तरह की हरकतों से डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए छात्र आंदोलनों के दौरान वह पेलेट गन और लाठीचार्ज का सामना कर चुकी हैं।

राजग का हिस्सा बने नए सांसदों से प्रधानमंत्री की मुलाकात,सोशल मीडिया के प्रभावी इस्तेमाल पर जोर

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हुए लोकसभा के सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। इस मुलाकात में शिवसेना (शिंदे) के 7, एनसीपीआई के 20, एनसीपी (अजीत पवार) के 2, उपेंद्र कुशवाहा समेत करीब 45 सांसद शामिल हुए। इस दौरान राजग में शामिल हुए सभी नए सांसदों को प्रधानमंत्री ने संसद में सक्रिय रूप से भाग लेने और स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता के प्रभावी इस्तेमाल की सलाह दी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य के लिए सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से संपर्क करें। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक सांसद से व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान बातचीत का कुछ हिस्सा मराठी भाषा में भी हुआ। प्रधानमंत्री न केवल मराठी भाषा समझते हैं बल्कि बोलते भी हैं। प्रधानमंत्री ने धाराशिव के सांसद ओमराजे निंबालकर से बातचीत के दौरान उनके योगाभ्यास के बारे में पूछा और स्वास्थ्य एवं दिनचर्या को लेकर चर्चा की। यह बैठक पूरी तरह से संवादात्मक और

विकास केंद्रित रही, जिसमें सांसदों को अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाने और जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सांसद शताब्दी रॉय ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को सोशल मीडिया पर प्रभावी तरीके से सक्रिय रहने पर जोर दिया। सोशल मीडिया के साथ अपने-अपने क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देने और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 40 वर्ष से अधिक उम्र के सांसदों को योग करने और साल में एक बार स्वास्थ्य की जांच कराने की सलाह भी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने किसानों और युवाओं से मिलने पर जोर दिया ताकि उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। इतिहास प्रधानमंत्री को उन्होंने माचा चाय के बारे में बताया। इस जापानी चाय के बारे में उन्होंने उत्सुकता से सुना। बैठक के बाद सांसदों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने में सकारात्मक तरीके भाग लेने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही बाधित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हंगामे के कारण नए सांसदों को सदन में बोलने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, जो उनके साथ अन्याय है।

पटना में युवक की मौत के बाद बवाल....

आगजनी से 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा

पटना,07 अगस्त 2026। बिहार की राजधानी पटना में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद हालात अचानक हिंसक हो गए। अगमकुआं थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी इलाके में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले बैठा।

गुस्साई भीड़ ने बस और पुलिस चौकी में लगाई आग

युवक की मौत से नाराज लोगों ने सबसे पहले दुर्घटना में शामिल बस को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद भीड़ ने पास स्थित पुलिस चेक पोस्ट में भी आगजनी की। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा यहीं नहीं थमा,बल्कि उन्होंने आसपास खड़ी कुछ अन्य बसों के शीशे तोड़ दिए और कई दोपहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। इलाके में आगजनी और तोड़फोड़ के कारण अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस और पत्रकार भी बने निशाना : स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जब विभिन्न थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तो प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा। वहीं,घटनास्थल की कवरेज कर रहे पत्रकार भी भीड़ के निशाने पर आ गए। प्रदर्शनकारियों ने वीडियो बना रहे मीडिया कर्मियों पर भी पत्थर फेंके, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई।

पुलिस की तीन गाड़ियों को किया आग के हवाले : पुलिस के अनुसार, जीरो माइल इलाके के पास हुए इस सड़क हादसे के बाद भड़की हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की तीन जीपों में आग लगा दी। पुलिस वाहनों के जलने से मौके पर हालात और तनावपूर्ण हो गए। प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं,लेकिन इलाके में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

दमकल की टीम को भी हुई परेशानी

आगजनी की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची,लेकिन सड़क जाम और उग्र प्रदर्शन के कारण उन्हें घटनास्थल तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तनावपूर्ण माहौल के बीच दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बल की मदद से राहत कार्य जारी रखा। हिंसक प्रदर्शन और सड़क जाम के कारण पूरे इलाके में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। जानकारी के अनुसार, सड़क पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्कूल बसें भी जाम में फंस गईं, जिससे बच्चों और अभिभावकों को काफी दिक्कत हुई।

40 साल पुराने बोफोर्स घोटाले की फाइल बंद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आखिरी अपील

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। देश के सबसे चर्चित और लंबे समय तक चले बोफोर्स घोटाले का कानूनी अध्याय अब पूरी तरह समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अंतिम याचिका खारिज कर दी, जिसमें हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही करीब 40 साल पुराने इस मामले का कानूनी अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुजा ब्रदर्स को बरी करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 2005 के फैसले के खिलाफ दायर अंतिम अपील को भी खारिज कर दिया है। इसके साथ ही भारत के सबसे चर्चित और लंबे समय तक चलने वाले भ्रष्टाचार के मामलों में से एक बोफोर्स कांड का कानूनी अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है। मामले में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की बेंच ने याचिकाकर्ता (अधिवक्ता अजय के. अग्रवाल) की स्थगन की मांग को ठुकराते हुए मामले की आखिरी याचिका को खारिज कर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी इस मामले में अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही देरी के आधार पर खारिज कर दिया था। 1986 में हुए इस रक्षा सौदे का विवाद लगभग 40 साल तक अदालतों और भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा। यह पूरा मामला 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुए 1,437 करोड़ रुपये के उस समझौते से जुड़ा है, जिसके तहत भारतीय सेना के लिए 400 हॉवित्जर तोपें खरीदी जानी थीं। साल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने यह सनसनीखेज खुलासा किया कि इस सौदे को हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को अवैध कमीशन दिए गए थे।

यूपीआई पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया साफ

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लागू किए जाने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट व्यवस्था लागू होती है तो इसका सीधा असर केवल व्यापारियों यानी मर्चेंट्स पर पड़ेगा। आम यूपीआई यूजर्स से किसी भी तरह का शुल्क वसूलने की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बैंकों और फिनटेक कंपनियों को लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर,सुरक्षा और नई तकनीक पर निवेश करना पड़ता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट से मिलने वाला सहयोग

डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जिसका फायदा अंततः सभी यूपीआई उपयोगकर्ताओं को मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने को लेकर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस विषय पर फैसला यूपीआई और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है, जब संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026 को मंजूरी मिलती है। इस प्रस्तावित विधेयक में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 10 में संशोधन करने की बात कही गई है। यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर राजनीतिक बहस तब तेज हुई जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया था कि नया विधेयक यूपीआई ट्रांजैक्शन को बिना शुल्क रखने वाली कानूनी व्यवस्था को कमजोर कर सकता है।जयराम रमेश ने कहा था कि अगर यह बदलाव लागू होता है तो भविष्य में सभी तरह के यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने का रास्ता खुल सकता है। उन्होंने आशंका जताई थी कि इसका अंतिम बोझ आम ग्राहकों पर पड़ सकता है और लोगों को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए शुल्क देना पड़ सकता है। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के इन दावों को गलत और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर संसद में तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए, न कि ऐसी बातें फैलानी चाहिए जिनसे लोगों के बीच भ्रम पैदा हो।वित्त मंत्री ने दोहराया कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है,जिसके तहत आम यूपीआई ग्राहकों से किसी भी प्रकार का चार्ज लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल भुगतान को आम लोगों के लिए आसान और सुलभ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने को लेकर चर्चा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के बयान के बाद शुरू हुई थी। उन्होंने कहा था कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने में एक निश्चित लागत आती है और किसी न किसी माध्यम से इस लागत को पूरा करना पड़ता है।हालांकि, आरबीआई गवर्नर ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि इस लागत का भार किस पर डाला जाएगा।

संपादकीय

अगर मैं मुख्यमंत्री का सलाहकार होता...
तो सत्ता बचाने नहीं...
विश्वास जीतने की सलाह देता...

लोकतंत्र में सरकारें केवल घोषणाओं से नहीं,बल्कि जनता के अनुभव से बनती और बिगड़ती हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले सड़कें बनवाना, योजनाओं की बौछार करना और विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च कर देना अब उतना प्रभावी नहीं रह गया है। आज का मतदाता पहले से कहीं अधिक जागरूक है। वह देखता है कि सरकार ने पूरे कार्यकाल में क्या किया,क्या नहीं किया और उसके जीवन में वास्तव में क्या बदलाव आया।

यदि मुझे मुख्यमंत्री का सलाहकार बनने का अवसर मिले,तो मेरी पहली सलाह यही होगी कि अगला चुनाव जीतने की रणनीति मत बनाइए,बल्कि ऐसा शासन दीजिए कि जनता खुद आपको दोबारा चुनना चाहे।

सबसे पहले सरकार को कानून-व्यवस्था पर पूरी ताकत लगानी चाहिए। यदि किसी राज्य में आम नागरिक,व्यापारी,महिलाएं और निवेशक स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते,तो विकास के सारे दावे कमजोर पड़ जाते हैं। अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो,उसके विरुद्ध निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई जनता का विश्वास बढ़ाती है। कानून का राज केवल भाषणों में नहीं,जमीन पर दिखाई देना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार होनी चाहिए। जनता यह मानने लगी है कि बिना पैसे या सिफारिश के सरकारी काम होना कठिन है। यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार कम करना चाहती है,तो केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। बड़े अधिकारियों, प्रभावशाली लोगों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भ्रष्ट तंत्र पर भी समान कठोरता दिखानी होगी। जब जनता देखेगी कि कानून सबके लिए बराबर है,तभी सरकार की विश्वसनीयता बढ़ेगी।

तीसरी सलाह होगी कि सरकारी कार्यालयों को जनता के लिए आसान बनाया जाए। आज भी एक सामान्य नागरिक को प्रमाण-पत्र,नामांतरण,सीमांकन,पेंशन, बिजली,पानी या राजस्व संबंधी कार्यों के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि हर सेवा समय-सीमा में मिले और अधिकारी जवाबदेह हों,तो यह किसी भी चुनावी घोषणा से अधिक प्रभावी उपलब्धि होगी।

युवा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। उन्हें केवल भत्ते नहीं, बल्कि रोजगार,कौशल और अवसर चाहिए। उद्योगों को आकर्षित करना, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना,स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। रोजगार का अवसर किसी भी राजनीतिक नारे से अधिक मजबूत संदेश देता है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केवल समर्थन मूल्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता। किसानों को सिंचाई,भंडारण,प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच की स्थायी व्यवस्था चाहिए। गांव मजबूत होंगे तो शहरों पर दबाव भी कम होगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार की असली परीक्षा होती है। यदि सरकारी अस्पतालों में दवाएं,डॉक्टर और जांच की सुविधा उपलब्ध हो तथा सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले,तो गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक सरकार के प्रति विश्वास विकसित होता है। इन क्षेत्रों में सुधार का राजनीतिक लाभ भले तुरंत न मिले, लेकिन सामाजिक लाभ सबसे अधिक होता है।

सरकार को यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया के दौर में पारदर्शिता ही सबसे बड़ी ताकत है। गलतियों को छिपाने के बजाय स्वीकार करना, समय पर जानकारी देना और जनता से संवाद बनाए रखना सरकार की विश्वसनीयता बढ़ाता है। आलोचना से डरने के बजाय उसे सुधार का अवसर मानना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार को केवल समर्थकों की नहीं,आलोचकों की भी सुननी चाहिए। लोकतंत्र में विरोधी आवाजें दुश्मन नहीं होतीं,बल्कि वे शासन की कमियां सामने लाने का काम करती हैं। यदि सरकार हर आलोचना को राजनीति मानकर खारिज कर देगी,तो धीरे-धीरे वास्तविक समस्याएं उसकी नजरों से ओझल हो जाएंगी।

चुनाव जीतने का सबसे आसान रास्ता मुफ्त योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि भरोसा जीतना है। जनता को यह महसूस होना चाहिए कि सरकार निष्पक्ष है, संवेदनशील है और निर्णय जनता के हित में ले रही है। जब नागरिक को न्याय, सम्मान और सुविधाएं बिना भेदभाव के मिलने लगें, तब सत्ता परिवर्तन की इच्छा स्वतः कमजोर पड़ जाती है।

किसी भी सरकार की सबसे बड़ी चुनावी रणनीति विज्ञापन नहीं, सुशासन होता है। जनता को भाषण नहीं, परिणाम चाहिए। यदि शासन ईमानदार,पारदर्शी और जवाबदेह होगा,तो सत्ता में वापसी के लिए अलग से रणनीति बनाने की आवश्यकता शायद ही पड़े। लोकतंत्र में अंततः वही सरकार लौटती है, जिस पर जनता को विश्वास रहता है।

सरकारी स्कूल बचेंगे,तो शिक्षा,संस्कार और संस्कृति भी बचेगी

डॉ. सत्यवान सौरभ
भिवानी, हरियाणा

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत उसके विशाल भवनों,चौड़ी सड़कों,ऊँची इमारतों या आर्थिक विकास दर से नहीं मापी जाती। किसी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शिक्षा व्यवस्था होती है। शिक्षा ही वह आधार है जिस पर सभ्यता, संस्कृति,लोकतंत्र,सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति का पूरा ढाँचा खड़ा होता है। यदि शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा,यदि शिक्षा कमजोर होगी तो उसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों तक दिखाई देगा...

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सरकारी विद्यालय केवल पढ़ाई के केंद्र नहीं हैं,बल्कि सामाजिक समानता के सबसे बड़े संस्थान भी हैं। यहाँ किसान का बेटा, मजदूर की बेटी,दुकानदार का बच्चा और सरकारी कर्मचारी का पुत्र एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यही वह व्यवस्था है जो समाज में समान अवसर की भावना को जन्म देती है। यदि यह व्यवस्था कमजोर पड़ती है,तो शिक्षा धीरे-धीरे आर्थिक क्षमता पर निर्भर हो जाती है और समाज दो हिस्सों में बँटने लगता है–एक वह जो महँगी शिक्षा खरीद सकता है और दूसरा वह जिसे सीमित अवसरों से ही संतोष करना पड़ता है।

आज दुर्भाग्य से यह धारणा तेजी से फैल रही है कि अच्छी शिक्षा केवल निजी विद्यालयों में ही मिल सकती है। अंग्रेज़ी माध्यम को गुणवत्ता का पर्याय मान लिया गया है। अभिभावक अपनी आय का बड़ा हिस्सा निजी विद्यालयों की फीस,परिवहन,पुस्तकों और अन्य खर्चों पर लगाने को मजबूर हैं। दूसरी ओर,सरकारी विद्यालयों के प्रति उदासीनता बढ़ी है। यह प्रवृत्ति केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं,बल्कि सामाजिक संतुलन का भी प्रश्न है।

यह सच है कि कुछ सरकारी विद्यालय संसाधनों,शिक्षकों की कमी या प्रशासनिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि देश के हजारों सरकारी विद्यालय उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। अनेक सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं,सेना,चिकित्सा,इंजीनियरिंग, खेल और शोध जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। समस्या पूरे सरकारी तंत्र की नहीं,बल्कि उसकी असमान गुणवत्ता,सार्वजनिक धारणा और निरंतर सहयोग की कमी की भी है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना,सही और गलत में अंतर करना सिखाना,संविधान के प्रति सम्मान विकसित करना और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव जगाना भी है। यदि शिक्षा केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित हो जाए तो वह अधूरी शिक्षा है। संस्कार,सहिष्णुता, अनुशासन,सहयोग और संवेदनशीलता जैसे मूल्य भी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा हैं।

सरकारी विद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। विविध सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों का एक साथ पढ़ना लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है। बच्चे एक-दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं, विविधता का सम्मान करना सीखते हैं और सामाजिक समरसता विकसित होती है। इसके विपरीत यदि शिक्षा पूरी तरह आर्थिक वर्गों में बँट जाएगी तो सामाजिक दूरी भी बढ़ेगी।

आज अपराध,नशाखोरी,हिंसा, साइबर अपराध और सामाजिक असहिष्णुता जैसी समस्याओं पर गंभीर चर्चा होती है। इन समस्याओं के अनेक कारण हैं–बेरोज़गारी,सामाजिक असमानता,पारिवारिक विघटन,अवसरों की कमी और मूल्य-आधारित शिक्षा का अभाव। यह कहना उचित नहीं होगा कि इन सभी समस्याओं का कारण केवल शिक्षा व्यवस्था है,लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि एक मजबूत, समावेशी और मूल्य-आधारित शिक्षा व्यवस्था इन चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

इसीलिए सरकारी विद्यालयों को केवल भवन,कमरे और फर्नीचर के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे सामाजिक परिवर्तन के केंद्र हैं। यदि इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित शिक्षक और समुदाय का सहयोग मिलेगा तो उनका प्रभाव केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि यदि निजी विद्यालय बेहतर हैं तो लोग सरकारी विद्यालयों की चिंता क्यों करें? इसका उत्तर बहुत सरल है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था कमजोर होने का प्रभाव अंततः पूरे समाज पर पड़ता है। जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल कुछ लोगों तक सीमित रह जाती है,तब अवसरों की असमानता बढ़ती है। असमानता बढ़ने पर सामाजिक तनाव,आर्थिक विषमता और असंतोष भी बढ़ते हैं। इसलिए सरकारी विद्यालयों की मजबूती केवल गरीबों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का हित है।

ग्रामीण भारत में सरकारी विद्यालयों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है। अनेक गाँवों में यही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहाँ बच्चों को शिक्षा का अवसर मिलता है। यदि इन विद्यालयों की गुणवत्ता बेहतर होगी तो गाँवों से पलायन कम होगा, स्थानीय प्रतिभाएँ आगे आएँगी और ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।

इसके विपरीत यदि ग्रामीण शिक्षा कमजोर होगी तो उसका प्रभाव रोजगार, कृषि,स्वास्थ्य और सामाजिक विकास तक दिखाई देगा।

शिक्षक इस पूरी व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। समाज को चाहिए कि वह शिक्षकों के प्रति सम्मान का वातावरण बनाए। साथ ही शिक्षकों का दायित्व भी है कि वे केवल पाठ्यक्रम पूरा करने तक सीमित न रहें,बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएँ। एक प्रेरित शिक्षक कई पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है।

अभिभावकों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विद्यालय केवल शिक्षकों के भरोसे नहीं चल सकते। यदि माता-पिता नियमित रूप से विद्यालय जाएँ, शिक्षकों से संवाद करें,बच्चों की पढ़ाई में रुचि लें और विद्यालय की गतिविधियों में भाग लें, तो शिक्षा का स्तर स्वतः बेहतर होगा। विद्यालय और परिवार का सहयोग ही सफल शिक्षा की कुंजी है।

स्थानीय समाज,पंचायतें, पूर्व विद्यार्थी,सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि भी सरकारी विद्यालयों के विकास में भागीदार बन सकते हैं। पुस्तकालय,खेल सामग्री,पौधारोपण, स्वच्छता अभियान,करियर मार्गदर्शन और डिजिटल संसाधनों जैसी अनेक पहलें सामुदायिक सहयोग से संभव हैं। जब पूरा समाज विद्यालय को अपना समझता है, तब विद्यालय भी समाज का गौरव बन जाता है।

सरकारों की जिम्मेदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, आधुनिक प्रयोगशालाएँ,डिजिटल कक्षाएँ, पुस्तकालय,खेल सुविधाएँ, सुरक्षित भवन, स्वच्छ पेयजल और नियमित प्रशिक्षण जैसी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करनी होंगी। शिक्षा पर किया गया व्यय खर्च नहीं, बल्कि भविष्य में किया गया निवेश होता है।

नई शिक्षा नीति ने भी मातृभाषा, कौशल विकास,समग्र शिक्षा और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया है। सरकारी विद्यालय इस दृष्टि को सबसे प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं,क्योंकि वे समाज की वास्तविक आवश्यकताओं के सबसे निकट हैं। यदि इन विद्यालयों को पर्याप्त संसाधन और सामाजिक विश्वास मिले तो वे राष्ट्रीय विकास की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं।

हमें यह भी समझना होगा कि अंग्रेज़ी भाषा सीखना उपयोगी है,लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल अंग्रेज़ी माध्यम नहीं है। ज्ञान,तर्कशक्ति,वैज्ञानिक सोच,नैतिकता और रचनात्मकता किसी एक भाषा की बपौती नहीं हैं। मातृभाषा में मजबूत आधार और अन्य भाषाओं का ज्ञान–दोनों मिलकर विद्यार्थियों को अधिक सक्षम बनाते हैं।

आज आवश्यकता दोषारोपण की नहीं, बल्कि सहभागिता की है। केवल सरकार को दोष देने या केवल शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराने से समाधान नहीं निकलेगा। शिक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार,शिक्षक,अभिभावक,विद्यार्थी और समाज–सभी को अपनी-अपनी भूमिका निभानी होगी।

यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ संवेदनशील,शिक्षित,संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक बनें,तो हमें सरकारी विद्यालयों को मजबूत बनाना ही होगा। यह केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि लोकतंत्र,सामाजिक न्याय,समान अवसर और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का प्रश्न भी है।

सरकारी विद्यालय बचाना किसी एक वर्ग का अभियान नहीं,बल्कि पूरे राष्ट्र का दायित्व है। जब सरकारी विद्यालय मजबूत होंगे,तब शिक्षा मजबूत होगी;शिक्षा मजबूत होगी तो संस्कार मजबूत होंगे;संस्कार मजबूत होंगे तो संस्कृति सुरक्षित रहेगी; और जब संस्कृति सुरक्षित रहेगी,तभी राष्ट्र का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा।

सरकारी विद्यालयों की घंटी केवल कक्षा शुरू होने का संकेत नहीं देती, बल्कि वह एक ऐसे भारत की आशा जगाती है जहाँ हर बच्चे को समान अवसर मिले,हर परिवार को शिक्षा का विश्वास मिले और हर नागरिक को अपने देश के भविष्य पर गर्व हो। इसलिए आइए,सरकारी विद्यालयों को केवल सरकार का नहीं,अपना विद्यालय मानें। क्योंकि यदि सरकारी स्कूल बचेंगे,तो शिक्षा भी बचेगी,संस्कार भी बचेंगे और हमारी साझा संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी।

गुजरात में चांदीपुरा वायरस के प्रकोप की चुनौतियाँ,वैज्ञानिक तथ्य और निवारण के मार्ग

दुर्गेश राय
गोरखपुर, उत्तरप्रदेश

गुजरात में मानसूनी नमी के साथ ही चांदीपुरा वायरस के मामलों ने एक बार फिर जनस्वास्थ्य और प्रशासन के समक्ष गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया के अनुसार,संदिग्ध लक्षणों वाले 184 नमूनों में से 35 मरीजों में चांदीपुरा वायरस की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है,जबकि इस घातक संक्रमण के कारण अब तक 22 बच्चों की जान जा चुकी है। गुजरात में अचानक इस प्रकोप के बढ़ने का मुख्य कारण मानसूनी मौसम के दौरान इसके प्राथमिक वाहक सैंडफ्लाई (रेत मक्खी) की आबादी में हुई तीव्र वृद्धि माना जा रहा है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए राज्यभर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सिविल अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है, जहाँ प्रभावित बच्चों के त्वरित उपचार हेतु वेंटिलेटर व ऑक्सीजन सुविधाओं से युक्त विशेष आईसीयू वार्ड बनाए गए हैं।

प्रकोप की विकराल होती स्थिति से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल को गुजरात और राजस्थान में तैनात कर दिया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एन. सी. डी. सी.),भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) और पशु पालन एवं डेयरी विभाग (डी. ए. एच. डी.) के विशेषज्ञों से बनी यह बहु विषयक टीम महामारी विज्ञान, नैदानिक प्रबंधन,प्रयोगशाला समन्वय और वेक्टर नियंत्रण में राज्य सरकारों का सहयोग कर रही है। एन.सी.डी.सी. के सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र को भी सक्रिय किया गया है। यह संपूर्ण प्रयास एक समन्वित वन हेल्थ दृष्टिकोण को दर्शाता है,जिसके तहत मानव, पशु और कीट निगरानी को एक साथ एकीकृत करके वायरस को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चांदीपुरा वायरस मुख्य रूप से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निशाना बनाने वाला एक अत्यंत तीव्र और घातक रोगजनक है। इसकी प्रथम बार पहचान वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के

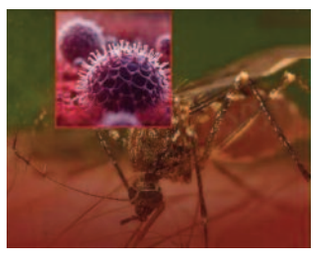

चांदीपुरा गाँव में हुई थी,जिसके आधार पर इसका नामकरण किया गया। जैविक रूप से यह रैबडोविरिडे परिवार का सदस्य है। इसी कुल में रेबीज का वायरस भी आता है। इसका जीनोम स्ट्रैंडेड-आरएनए प्रकार का होता है।

संक्रमण के प्रसार का माध्यम पूरी तरह कीट-जनित (वेक्टर-बॉर्न) होता है, जिसका अर्थ है कि यह सीधे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता। वर्षा ऋतु में जब संक्रमित सैंडफ्लाई या मच्छर किसी बच्चे को काटते हैं,तो विषाणु रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। इसके पश्चात यह रक्त बाधा को पार करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर सीधा हमला बोलता है,जिससे मस्तिष्क की कोशिकाओं में तीव्र सूजन आ जाती है। चिकित्सा विज्ञान में इस स्थिति को एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम अथवा मस्तिष्क ज्वर कहा जाता है।

हालाँकि सैंडफ्लाई को मुख्य वाहक माना जाता है,लेकिन वैज्ञानिक अब व्यापक अनुसंधानों के ज़रिए यह भी जांच रहे हैं कि क्या मच्छर, टिक और माइट जैसे अन्य आथ्रोपोड भी इसके प्रसार में भूमिका निभाते हैं। वर्तमान जांच में गुजरात के 2024 के प्रकोप से मिले उन सबकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है,जहाँ सैंडफ्लाई के नमूनों में वायरस न मिलने के कारण किसी एक वाहक को निर्णायक रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सका था। इसके अतिरिक्त, यह पता लगाने के लिए पशु निगरानी भी बढ़ाई गई है कि क्या गाय,भैंस और बकरियाँ जैसे घरेलू पशु इस वायरस के वाहक बन रहे हैं;इसके तहत पशुओं के रक्त और दूध के लगभग 70 नमूनों का विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही, गांधीनगर स्थित गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (जी.बी.आर.सी.) में वायरस के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण के दौरान प्रारंभिक विश्लेषण में कुछ मामूली आनुवंशिक भिन्नताएं भी पाई गई हैं।

नो बीमा,नो पेट्रोल...

संजय एम. तराणेकर
इन्दौर,मध्यप्रदेश

नो बीमा,नो पेट्रोल,सड़कों पे फिर कैसा रोल?
नियम सबके लिए हैं,क्यों हों उनमें कोई होल?
वाहन ले निकल पड़े जब,जिम्मेदारी भूल गए,
अपनी ही नहीं,राहगीरों की सुरक्षा से दूर गए।
बीमा सिर्फ कागज़ नहीं,विश्वास की वो ढाल है,
दुर्घटना की घड़ी में,परिवार का संबल हाल है।
पेट्रोल बिन रथ न दौड़े,बीमा बिन सफ़र अधूरा,
नियमों का सम्मान करेंगे,तब बनेगा भारत पूरा।
सड़कें केवल राह नहीं हैं,जीवन की यह डोर हैं,
ये नो बीमा,नो पेट्रोल,जिम्मेदारी की ओर है।
आओ मिलकर प्रण लें,नियमों का सम्मान करें,
सुरक्षित यात्रा व जीवन,देश का अभिमान करें।

मजबूरी

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक,हरियाणा

मैं आसमान में उड़ना चाहता हूं
पर मेरे पास पंख नहीं है!
मैं दिल खोलकर
दान करना चाहता हूं
पर मेरे पास उतना
धन ही नहीं है!
मैं सब लोगों को
अपना बनाना चाहता हूं
पर सब लोग अपना बनाने के
काबिल नहीं है!
मैं बच्चों की तरह
मासूम बनना चाहता हूं
लेकिन चालाक दुनिया
इजाजत नहीं देती!
मैं सभी धार्मिक लोगों की
इज्जत करना चाहता हूं
लेकिन कुछ पाखंडी लोग
मेरा रास्ता रोकते हैं।
मैं जीवन में सब्र,
संयम से रहना चाहता हूं
पर कई बार हालात
बहुत मजबूर कर देते हैं।
मेरा हर विषय का ज्ञान तो
बहुत सीमित है
इसलिए जहां संभव हो
कुछ सीखता रहता हूं।
मैं जीवन में करना तो
बहुत कुछ चाहता हूं
मगर कोई ना कोई मजबूरी
आड़े आ जाती है।

सावन सिर्फ़ एक ऋतु का नाम नहीं,यह हमारे संस्कारों,भावनाओं और जीवन के उत्सव का नाम है...

मुश्ताक अहमद
हरदा,मध्यप्रदेश

प्रकृति जब अपनी तमाम नेमतों और रंगों के साथ खुलकर मुस्कुराती है,तो वह पल केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं, बल्कि मानव मन के प्रस्फुटन का होता है। भारतीय संस्कृति और जीवन-पद्धति में सावन (श्रावण मास) केवल एक महीना नहीं,बल्कि एक जीवंत अहसास है,उमंग,हर्ष,खुशी,मुस्कान, हरियाली और उल्लास का एक ऐसा महाकुंभ,जो सूखी धरती और बुझे हुए दिलों में एक साथ नई जान फूंक देता है। शहरों की चकाचौंध और कंक्रीट के जंगलों से बहुत दूर, जहाँ दिल आज भी मिट्टी की सौंधी खुशबू से धड़कते हैं,वहाँ सावन प्राणों का स्पंदन बनकर उतरता है। जब आसमान में काले घटाएँ घिरती हैं और रिमझिम फुहारें धरती को चूमती हैं,तो गाँव की चौपालों से लेकर खेतों की मेड़ों तक एक अनूठा संगीत गूँज उठता है। यह मौसम प्रकृति के श्रृंगार के साथ-साथ हमारी प्राचीन भारतीय परंपराओं, लोक-संस्कृति और अटूट भावनात्मक रिश्तों का एक जीवंत दस्तावेज है।

धरा का कायाकल्प और लहलहाती फ़सलें

जेठ और आषाढ़ की तपती दोपहरी में जब खेत तड़प रहे होते हैं और हर तरफ हाहाकार मचा होता है, तब सावन अपने साथ राहत का अमृत लेकर आता है। पहली मानसूनी फुहार के साथ ही सूखी और बंजर दिखने वाली ज़मीन पर रातों-रात मखमली हरी घास की चादर बिछ जाती है।

गाँव के छोर पर खड़े बबूल और पीपल के पुराने पेड़ नहाकर ऐसे चमक उठते हैं मानो किसी ने उन्हें नया श्रृंगार दे दिया हो। दूर-दूर तक फैली ज़मीन पर जब लहलहाती फ़सलें सिर उठाती हैं, और धान के हरे-भरे पौधे हवा के झोंकों के साथ झूमते हैं, तो किसानों के मुरझाए चेहरों पर जो सुकून भरी मुस्कान तैरती है,वह दुनिया की किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे धरती माता अपनी हरी चुनरी ओढ़कर इठला रही हो।

सावन की आत्मा,भुजरिया पर्व और ग्रामीण भाईचारा

सावन की बात हो और ग्रामीण भारत की माटी से जुड़े पवित्र पर्व भुजरिया (कजलियां) का जिक्र न हो,तो यह आलेख अधूरा रहेगा। नागपंचमी के बाद और रक्षाबंधन के आसपास मनाया जाने वाला यह पर्व ग्रामीण संस्कृति की

वास्तविक आत्मा है।

सावन के शुरुआती दिनों में बहनें और माताएँ घरों में बांस की छोटी टोकरियों या बर्तनों में साफ़-सुथरी मिट्टी डालकर गेहूं या जौ बोती हैं। इसे एकांत और पवित्र स्थान पर रखकर रोज़ सप्रेम सींचा जाता है। कुछ ही दिनों में जब वे नन्हें, सुनहरे-हरे तिनके उगकर बाहर आते हैं, तो उन्हें भुजरिया कहा जाता है। रक्षाबंधन के दिन या उसके अगले दिन इन भुजरिया के पौधों को बहुत ही श्रद्धा और सत्कार के साथ निकाला जाता है। गाँव की गलियों में ढोल-ढमाकों और पारंपरिक लोकगीतों की गूँज के साथ महिलाएँ और पुरुष इन्हें सिर पर रखकर नदियों तक ले जाते हैं। बुजुर्गों के पैर छूकर यह हरी-भरी भुजरिया देकर आशीर्वाद लिया जाता है।

यह पल केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि पीढ़ियों के बीच के आदर, भाईचारे और प्रेम का ऐसा भावनात्मक बंधन है,जो दिलों की सभी दूरियों को मिटा देता है। इस एक मुट्ठी हरियाली और आशीर्वाद के आदान-प्रदान में पूरा गाँव एक परिवार बन जाता है।

रिमझिम बारिश और लोक-जीवन के रंग

सावन की पहचान इसकी रिमझिम बारिश से है। यह वह बारिश नहीं जो आंधी-तूफान लाकर तबाही मचाए,यह तो एक धीमी,सुरीली और मद्धम फुहार है,जो सीधे मन के तारों को छेड़ जाती है। जब आसमान से अमृत रूपी जल बूंदों के रूप में गिरता है, तो सूखी मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुल जाती है। टप-टप गिरती बूंदों के साथ पपीहे की पी-कहां की टेर और मेंढकों की टर्र-टर्र मिलकर ऐसा प्राकृतिक संगीत रचती है, जिसे सुनकर सुध-बुध खो बैठना स्वाभाविक है।

इस मौसम में गाँव की बहुएँ और बेटियाँ मिलकर पेड़ों की डालियों पर झूला डालती हैं। झूले की रस्सी जब आसमान को छूने दौड़ती है,तो उनके गले से फूटे लोकगीत,कजरी और मल्हार–हवा में घुल जाते हैं। उन गीतों में मायके की याद होती है,सावन की उमंग होती है और प्रियतम के इंतज़ार की वो मीठी कसक होती है,जो आँखों में चमक और होठों पर मुस्कान ले आती है। चारों तरफ़ बिखरे रंगीन नज़ारे खेतों की हरियाली, लाल-हरी चूड़ियाँ, और आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष,मन को पूरी तरह मोह लेते हैं।

उल्लास और भावनाओं का संगम

सावन का यह महीना हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी धूप और तपन क्यों न आए,एक दिन प्रेम, भाईचारे और संतोष की फुहारें उसे हरा-भरा जरूर कर देती हैं। जब गाँव का हर व्यक्ति भुजरिया के बहाने गले मिलता है,जब बच्चे रिमझिम बारिश में कागज़ की नाव तैराते हैं, और जब बुजुर्ग नीम की छांव में बैठकर पुरानी यादें ताजा करते हैं,तब समझ आता है कि असली भारत इन्हीं गाँवों की सोंधी खुशबू और संस्कृति में बसता है। सावन सिर्फ़ एक ऋतु का नाम नहीं, यह हमारे संस्कारों,भावनाओं और जीवन के उत्सव का दूसरा नाम है। यह याद दिलाता है कि जीवन में संघर्ष के बाद उल्लास और उमंग के दिन अवश्य आते हैं। जब भी जीवन में निराशा घिरे,बस सावन की किसी रिमझिम शाम और अपनों के आत्मीय मिलन को याद कर लीजिए,मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो उठेगा।

सुविचार

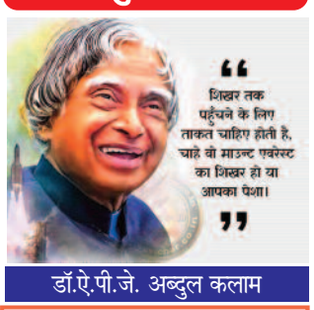

डॉ.ऐ.पी.जे. अब्दुल कलाम

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

CMYK

क्या मरीजों की बीमारी भी अब कमीशन तय करेगा? ब्लड टेस्ट की विश्वसनीयता पर उठते सवाल,डॉक्टर-लैब गठजोड़ की जांच जरूरी

राज्यसभा में राघव चड्ढा ने उठाया कमीशन का मुद्दा,देशभर में फर्जी ब्लड रिपोर्ट के मामले सामने आने के बाद अम्बिकापुर में भी पारदर्शिता और जांच की मांग तेज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्वास्थ्य सेवा का आधार मानी जाने वाली पैथोलॉजी जांचों की विश्वसनीयता पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा द्वारा डॉक्टरों और कुछ डायग्नोस्टिक लैब के कथित कमीशन तंत्र का मुद्दा उठाए जाने के बाद पूरे देश में इस विषय पर नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने सदन में कहा कि कुछ डॉक्टर मरीजों को विशेष लैब में जांच कराने के लिए भेजते हैं और बदले में कथित रूप से कमीशन, महंगे उपहार या विदेश यात्राओं जैसी सुविधाएं प्राप्त करते हैं। यदि ऐसे आरोप सही हैं तो यह केवल आर्थिक अनियमितता नहीं,बल्कि मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। इसी बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फर्जी ब्लड रिपोर्ट तैयार करने,बिना वास्तविक जांच के रिपोर्ट जारी करने तथा नामी लैब के नाम का दुरुपयोग करने जैसे मामलों का खुलासा भी हुआ है। इन घटनाओं ने मरीजों का भरोसा कमजोर किया है और स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

अलग-अलग लैब,अलग-अलग रिपोर्ट...आखिर सही कौन? एक वरिष्ठ पुस्तक विक्रेता विनीत सेठी ने दावा किया कि यदि एक ही व्यक्ति एक ही समय पर तीन अलग-अलग पैथोलॉजी लैब में समान रक्त जांच कराए तो कई बार तीनों रिपोर्टों में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिलता है। यह दावा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो यह सवाल स्वाभाविक है कि चिकित्सक उपचार किस रिपोर्ट के आधार पर करें और मरीज किस पर भरोसा करे। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि कुछ परीक्षणों में मशीन, परीक्षण विधि,रेफरेंस रेंज,सैंपल हैंडलिंग तथा जैविक कारणों से सीमित अंतर संभव है। लेकिन यदि अंतर असामान्य या चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण हो तो उसकी जांच आवश्यक है।

अम्बिकापुर में भी उठ रहा सवाल : अम्बिकापुर में भी समय-समय पर यह चर्चा होती रही है कि कुछ चिकित्सक विशेष लैब से ही जांच कराने की सलाह देते हैं। फिलहाल इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और किसी विशेष डॉक्टर या लैब के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है। फिर भी यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो संबंधित स्वास्थ्य विभाग को उनकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए।

सीएमएचओ की जिम्मेदारी

विशेषज्ञों का मानना है कि जिला स्वास्थ्य प्रशासन को निम्न बिंदुओं पर विशेष अभियान चलाना चाहिए–

- जिले की सभी पैथोलॉजी लैब का नियमित निरीक्षण।
- मान्यता, लाइसेंस और योग्य पैथोलॉजिस्ट की उपलब्धता की जांच।
- गुणवत्ता नियंत्रण और रिकॉर्ड का ऑडिट।
- शिकायत मिलने पर रिपोर्ट का पुनः सत्यापन।
- यदि कमीशन या अनियमितता के प्रमाण मिलें तो संबंधित नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई।

देशभर में सामने आए गंभीर मामले

देश के विभिन्न राज्यों में पुलिस और प्रशासन ने ऐसे मामलों का खुलासा किया है, जिनमें बिना परीक्षण के कंप्यूटर से रिपोर्ट तैयार करने,फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर लगाने तथा ब्रांडेड लैब के नाम का दुरुपयोग करने के आरोप सामने आए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रक्त जांच के क्षेत्र में बड़े कॉरपोरेट धोखाधड़ी के मामले सामने आ चुके हैं,जिससे यह स्पष्ट होता है कि लैब परीक्षणों की गुणवत्ता और निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

कमीशन का खेल मरीज पर भारी?

स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि किसी डॉक्टर और लैब के बीच आर्थिक लेन-देन या कमीशन की व्यवस्था होती है,तो अनावश्यक जांच लिखे जाने की आशंका बढ़ जाती है। इससे मरीज का आर्थिक बोझ बढ़ता है और कई बार अनावश्यक इलाज भी शुरू हो सकता है। यद्यपि सभी डॉक्टर और सभी लैब इस श्रेणी में नहीं आते। बड़ी संख्या में चिकित्सक और पैथोलॉजी विशेषज्ञ पूरी ईमानदारी और पेशेवर मानकों के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रमाण और निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

मरीज भी रहें सतर्क

मरीजों को चाहिए कि वे मान्यता प्राप्त लैब से ही जांच कराएं,रिपोर्ट का सत्यापन करें और यदि रिपोर्ट पर संदेह हो तो आवश्यकता पड़ने पर दूसरी विश्वसनीय लैब से पुनः जांच कराएं। उपचार केवल योग्य चिकित्सक की सलाह से ही लें।

सवाल व्यवस्था से है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं

स्वास्थ्य व्यवस्था में जनता का विश्वास सर्वोपरि है। यदि कुछ लोगों की वजह से पूरे चिकित्सा तंत्र की छवि प्रभावित हो रही है तो इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना आवश्यक है। यदि आरोप गलत हैं तो उन्हें भी तथ्यों के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए,और यदि सही हैं तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर मरीज इलाज के लिए अस्पताल जाता है, किसी कमीशन तंत्र का हिस्सा बनने के लिए नहीं।

कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री,आज रात 9 बजे से लागू होगा प्रतिबंध

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरगुजा पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों के आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध आज 7 अगस्त 2026 की रात 9:00 बजे से 10 अगस्त 2026 की दोपहर 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर शंकरघाट मंदिर से लुचकी घाट, चेंद्रा, रघुनाथपुर, बतौली तथा कांवड़ यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य यातायात को सुचारु बनाए रखना और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम करना है। प्रतिबंध अवधि में रामानुजगंज रोड पर ककना मोड़ से रामानुजगंज चौक (बंगाली चौक),बंगाली चौक से खरसिया नाका (भारत माता चौक),अम्बिकापुर-बतौली मार्ग तथा खरसिया रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश और निकासी पूरी तरह बंद रहेगी। पुलिस के अनुसार बिलासपुर, बनारस,सूरजपुर और बलरामपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों को 9 अगस्त दोपहर 12 बजे के बाद,जबकि रायगढ़ रोड की ओर जाने वाले

भारी वाहनों को 10 अगस्त दोपहर 12 बजे के बाद छोड़ा जाएगा। रामानुजगंज की ओर से आने वाले भारी वाहन ककना मोड़-कल्याणपुर मार्ग से अम्बिकापुर आ सकेंगे। रामानुजगंज जाने वाले भारी वाहन प्रताप रोड-कल्याणपुर-ककना मोड़ होकर आवागमन करेंगे। बिलासपुर रोड से बनारस जाने वाले वाहनों का आवागमन यथावत रहेगा। मनेन्द्रगढ़ रोड से आने वाले भारी वाहन बिलासपुर रोड एवं बनारस रोड की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। सरगुजा पुलिस ने सभी ट्रांसपोर्टरों एवं भारी वाहन चालकों से अपील की है कि निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन न भेजें तथा वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

संगीत संघ ने रफी साहब को दी सुरमई श्रद्धांजलि

'एक शाम मोहम्मद रफी के नाम' कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने बांधा समां, महापौर ने की सराहना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि पर संगीत संघ अम्बिकापुर के तत्वावधान में आयोजित 'एक शाम मोहम्मद रफी के नाम' कार्यक्रम में शहर के कलाकारों ने उनके अमर गीतों की सुमधुर प्रस्तुतियों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का आयोजन स्व. यूनुस खान जिमनास्टिक क्लब की स्मृति में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, भाजपा जिला महामंत्री विनोद हर्ष तथा जिमनास्टिक क्लब के संरक्षक मृगेंद्र सिंह देव उपस्थित रहे। शहर के गायक कलाकारों ने रफी साहब के लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। कार्यक्रम में संतोष दास सरल,फरीद बेग, राधेश्याम मानिकपुरी, इमरान खान, अश्मि वर्मा, विमल मंदिलवार, मुकुल रावत, मेघा रावत, सुप्रिया सिन्हा, कल्पना गुप्ता, राकेश मिश्रा, एस. रामटेके, राजेश सिंह, रेखा देवांगन, श्रवण पांडे, बबली पांडे, शैलेन्द्र श्रीवास्तव, मुमताज बेग, फरदीन, मीना मिंज, संजीव गणेश पुरकर, रेखा पुरकर, शिवम सिन्हा, लीला आगरे, प्रिया सिंह, मृदुल वर्मा, राजेश सोनी, मनीष श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव तथा उन्मेष मिश्रा ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। कलाकार सुधीर सिंह राणा ने बांसुरी वादन से कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया, जबकि अतिथि कलाकार गोपाल पांडे एवं स्वप्निल जायसवाल ने भी शानदार प्रस्तुति दी। महापौर मंजूषा भगत ने संगीत संघ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि रफी साहब की पुण्यतिथि पर शहर के कलाकारों ने उत्कृष्ट प्रस्तुति दी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रतिभाओं को ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से निरंतर मंच और अवसर मिलना चाहिए। कार्यक्रम का संयुक्त संचालन मीना वर्मा एवं शक्ति वर्मा ने किया। आभार प्रदर्शन संगीत संघ के अध्यक्ष संतोष दास सरल ने किया, जबकि आयोजन का संयोजन जयेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी, गणमान्य नागरिक एवं सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोग उपस्थित रहे।

ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाली सीएसए विद्यावती टोप्पो के परिजनों को एचपीसीएल ने दी 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने मानवीय पहल करते हुए ड्यूटी के दौरान पिछले वर्ष हुई हत्या की शिकार कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव (सीएसए) विद्यावती टोप्पो के परिजनों को 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की। घटना के लगभग दस माह बाद आयोजित कार्यक्रम में मृतका के माता-पिता को चेक सौंपकर कंपनी ने उनके प्रति अपनी संवेदना और जिम्मेदारी व्यक्त की। मैनपाट के सैला रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में एचपीसीएल के महाप्रबंधक समीर एक्का एवं मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अर्नब चटर्जी ने मृतका के पिता हीरालाल उरांव तथा माता सुमंती को 20 लाख रुपये का चेक सौंपा। इस अवसर पर महाप्रबंधक समीर एक्का ने कहा कि सीएसए एचपीसीएल परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य होता है,जो हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। उन्होंने कहा कि यह अनुग्रह राशि परिवार के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता और सहयोग का प्रतीक है। कार्यक्रम में दिवंगत विद्यावती टोप्पो की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र सिंह ने किया,जबकि आभार प्रदर्शन संदीप त्रिपाठी ने किया। इस दौरान नंगे पांव सत्याग्रह के राजेश सिंह सिसोदिया,मृतका की बहन सविता टोप्पो,अन्य परिजन,अंबिकापुर विक्रय क्षेत्र के डीलर, कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव तथा एचपीसीएल के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर के कन्या परिसर रोड स्थित माखन विहार गेट नंबर-3 के पास घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना की पूरी वारदात पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में एक अज्ञात युवक देर रात बाइक चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रार्थी अजय सिंह ने पुलिस को बताया कि वह सरस्वती कॉलेज, सुभाषनगर में बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। उसके नाना बलजीत सिंह मरावी के नाम से पंजीकृत बाइक घर के बाहर खड़ी रहती थी। 29 जुलाई की रात भोजन करने के बाद वह सो गया। अगले दिन सुबह करीब 6 बजे उठकर देखा तो बाइक अपने स्थान पर नहीं थी।

ब्रह्माकुमारीज के 10 करोड़ नशामुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का अंबिकापुर में शुभारंभ

पहले दिन 12 हजार विद्यार्थियों ने ली नशामुक्ति की शपथ

20 अगस्त तक संभागभर में चलेंगे जागरूकता कार्यक्रम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी की पावन स्मृति में संचालित 10 करोड़ नशामुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान का शुक्रवार को अंबिकापुर सहित पूरे सरगुजा संभाग में शुभारंभ किया गया। अभियान के पहले ही दिन विभिन्न विद्यालयों में करीब 12 हजार विद्यार्थियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। अभियान की शुरुआत शहर में निकाली गई जागरूकता रैली से हुई। रैली को भगवानपुर स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉ. अपूर्व तथा मदारी आर्ट के संचालक आनंद गुप्ता ने शिव ध्वज दिखाकर रवाना किया। ब्रह्माकुमारीज अंबिकापुर सेवाकेंद्र की संचालिका बीके विद्या दीदी ने बताया कि यह महाअभियान 6 अगस्त से 20 अगस्त तक सरगुजा संभाग में संचालित किया जाएगा। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी एवं निजी कार्यालयों, सामाजिक संस्थाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशा न करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी। पहले दिन शासकीय मल्टीपरपज स्कूल, मोंटफोर्ट स्कूल, नेहरू विद्या मंदिर, ब्राइट स्टार स्कूल, सारगवा, मेंड्राकला, बोदा, नमनाकला, ठाकुरपुर सहित बतौली, बलरामपुर, बैकुंठपुर एवं सूरजपुर के अनेक विद्यालयों में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक नशामुक्ति की शपथ ली। अभियान के अंतर्गत पहले दिन लगभग 12 हजार विद्यार्थियों तक संदेश पहुंचाया गया। इस अभियान में बीके रेखा बहन, बीके ममता बहन, बीके संजू बहन, बीके उमा बहन, बीके पार्वती बहन, बीके सरिता, बीके मंजू बहन, बीके अहिल्या बहन, बीके लल्लू भाई, बीके मनोज भाई एवं बीके उमेश भाई सहित अनेक ब्रह्माकुमारी भाई-बहनों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। बीके विद्या दीदी ने बताया कि अंबिकापुर के अलावा संभाग के अन्य 11 ब्रह्माकुमारीज सेवाकेंद्रों के माध्यम से भी यह अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को नशामुक्ति के प्रति जागरूक कर स्वस्थ और संस्कारित समाज के निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

स्वतंत्रता दिवस पर सेवा किटी समूह आयोजित करेगा निबंध लेखन प्रतियोगिता

स्वतंत्र भारत में युवा आक्रोश : कारण और समाधान' विषय पर विद्यार्थी रखेंगे अपने विचार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस के पूर्व हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेवा किटी समूह द्वारा विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरूकता एवं चिंतनशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का विषय 'स्वतंत्र भारत में युवा आक्रोश : कारण और समाधान' रखा गया है। इसमें हाईस्कूल एवं महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। आयोजन 9 अगस्त (रविवार) को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक शासकीय कन्या शाला, अंबिकापुर में आयोजित होगा। प्रतियोगिता के सफल संचालन की जिम्मेदारी दीपमाला सिंह, सुनीता दास, हिना परवीन, बोनी डे, अंजना परिहार एवं स्मिता तिवारी को सौंपी गई है। प्रतियोगिता के विजेताओं को स्मृति चिन्ह, प्रमाणपत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। सेवा किटी समूह की संयोजिका वंदना दत्ता ने जिले के सभी हाईस्कूल एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों से अधिक से अधिक संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने विचारों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देने की अपील की है।

अंबिकापुर के सीएसपी पर एक करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप,दिल्ली की विशेष अदालत ने जारी किया नोटिस

हवाला के जरिए घूस लेने का आरोप,डीजीपी छत्तीसगढ़ और सीबीआई निदेशक से मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर के पुलिस अधीक्षक समेत तीन पुलिस अधिकारियों पर हवाला के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत लेने के गंभीर आरोपों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने शिकायत पर प्रथम दृष्टया संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी),सीबीआई निदेशक तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही डीजीपी से

पूरे मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट और सीबीआई से शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/सीबीआई-11 सुधांशु कौशिक की अदालत में 1 जुलाई 2026 को आकाश कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 175(3) के तहत नई शिकायत प्रस्तुत की गई। अदालत ने शिकायत प्राप्त होने के बाद उसे जांच के लिए पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनमीत सिंह उपस्थित रहे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अंबिकापुर में पदस्थ एक भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी राहुल बंसल ने साइबर थाना सरगुजा में पदस्थ दो उप निरीक्षकों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस षड्यंत्र के तहत हवाला चैनल के माध्यम से एक करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत की मांग की गई और उसे स्वीकार भी किया गया। शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 7ए तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 308 एवं 351 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत के साथ शपथ-पत्र भी संलग्न किया गया है।

सीबीआई से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का दावा : अदालत में शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने 8 जून 2026 को सीबीआई निदेशक को लिखित शिकायत देकर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी,लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत की प्रति भी अदालत में प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता का भी आरोप लगाया।

एसपी बोले आईजी सर बताएंगे : इस मामले में एसपी राजेश अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला रेंज थाने का है। आईजी सर ही बता पाएंगे। पक्ष जानने आईजी दीपक झा के मोबाइल पर कॉल किया गया तो उन्होंने रिसिव नहीं किया।

CMYK

जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन...पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने पौधारोपण कर 'एक पेड़ माँ के नाम 3.0'' अभियान की शुरुआत किया

यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ,सुरक्षित एवं समृद्ध पर्यावरण सुनिश्चित करने का एक सार्थक प्रयास है,पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं : मंत्री अग्रवाल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को अम्बिकापुर के हर्राटिकरा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने पौधारोपण कर ''एक पेड़ मां के नाम 3.0'' अभियान का शुभारंभ किया और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राज्य युवा अयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर,महापौर अम्बिकापुर श्रीमती मंजुषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती निरूपा सिंह,सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, वनमंडलाधिकारी अभिषेक जोगावत,उप वनमण्डलाधिकारी अम्बिकापुर सुश्वेता कम्बोज,एसडीएम अम्बिकापुर बनसिंह नेताम उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंत्री अग्रवाल ने एयर लेयरिंग से तैयार किए गए पीपल के वृक्ष का रोपण किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं तथा उनका संरक्षण करें। इस अवसर पर उन्होंने विशेष रूप से विवाह समारोहों के दौरान मड़वा (मंडप) निर्माण के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति संरक्षण का यह अभियान आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं समृद्ध पर्यावरण सुनिश्चित करने का एक सार्थक प्रयास है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन सरकार पर्यावरण संरक्षण,जैव विविधता के संवर्धन तथा जन-जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आइए,हम सभी अधिक से अधिक पौधे लगाएं,उनका संरक्षण करें और प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग द्वारा रेस्क्यू की गई पक्षी ब्लैक काइट (काली चील) को उसके प्राकृतिक आवास मुक्त किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में कुल 450 पौधों का रोपण किया गया। जिसमें मुख्य प्रजाति गुलर, पीपल,शीशम,गुल्लू,बरगद आदि पौधों का रोपण किया गया। जिसमें जन प्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, एनसीसी के छात्र-छात्राओं, विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधियों, वन प्रबंधन समितियों के सदस्य एवं ग्रामीणों के द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान ट्री एटीएम के माध्यम से पौधा रोपण किया गया तथा किसान वृक्ष मित्र योजना के तहत हितग्राहियों को नीलगिरी पौधों का वितरण किया गया। बताया गया कि सरगुजा

वनमण्डल में इस वर्ष अब तक कुल 31800 पौधों का रोपण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा चुका है।

तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर भाजपा की बैठक सम्पन्न,16 मंडलों को सौंपे गए पवित्र माटी युक्त कलश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी जिला सरगुजा द्वारा 9 से 14 अगस्त तक आयोजित होने वाले 'तिरंगा यात्रा-हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियों को लेकर संकल्प भवन स्थित भाजपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान की रूपरेखा, जिम्मेदारियों एवं कार्यक्रमों के सफल संचालन पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से लाई गई पवित्र माटी युक्त कलश जिले के सभी 16 मंडल अध्यक्षों को सौंपे गए। जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि तिरंगा यात्रा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि समलाया मंदिर एवं मल्टीपरपज हाई स्कूल मैदान से तिरंगा यात्राएं प्रारंभ होकर महामाया चौक से संयुक्त रूप से स्वामी विवेकानंद चौक तक निकाली जाएंगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि यह अभियान नागरिकों में राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत करेगा। जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने कहा कि तिरंगा यात्रा और समरसता संकल्प अभियान सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रभावना को सशक्त बनाने का माध्यम हैं। बैठक को संतोष दास एवं निश्चल प्रताप सिंह ने भी संबोधित किया। संचालन अरुणा सिंह ने तथा आभार चंद्रिका यादव ने व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

ग्रामीण अंचल की बेटियों को शिक्षा से जोडना है सरस्वती साइकिल का उद्देश्य : शकुंतला

हायर सेकेंडरी स्कूल सरहरी में प्रतापपुर विधायक शकुंतला ने वितरित किया सरस्वती साइकिल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरहरी में सरस्वती साइकिल वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते उपस्थित रहीं। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रतापपुर मंडल अध्यक्ष मुकेश तायल, शासकीय अधिवक्ता अक्षय तिवारी, जनपद सदस्य कुंती शिवपाल कुशवाहा, पोड़ी सरपंच रूप मिंज तथा सरहरी उप सरपंच उषा देवी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कक्षा नवमीं में अध्ययनरत 24 छात्राओं को साइकिलें वितरित की गईं। कार्यक्रम में विधायक शकुंतला पोर्ते ने कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा में विकासखंड स्तर पर 'टॉप टेन' सूची में स्थान बनाने वाले दो होनहार विद्यार्थियों प्राची यादव एवं नितिन काशीपुरी को 1100-1100 रुपये की प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही, विद्यालय परिसर के विकास एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विधायक ने विद्यालय में चबूतरा निर्माण हेतु 2 लाख रुपये की राशि देने की घोषणा की। छात्राओं को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि राज्य सरकार की सरस्वती साइकिल योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचल की बेटियों को शिक्षा से जोड़ना और उनकी पढ़ाई में आने वाली दूरी की बाधा को समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि आज की छात्राएं कल का भविष्य हैं। यदि उन्हें बेहतर अवसर और सुविधाएं मिलेंगी तो वे शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएंगी और प्रदेश के साथ-साथ अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष मुकेश तायल एवं शासकीय अधिवक्ता अक्षय तिवारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन विद्यालय के प्राचार्य दिलीप तिवारी ने दिया। मंच का सफल संचालन राज्यपाल पुरस्कृत व्याख्याता अजय कुमार चतुर्वेदी द्वारा किया गया तथा अंत में आभार प्रदर्शन विजय भारती ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के समस्त स्टाफ का भरपूर सहयोग रहा।

एचपीवी विशेष टीकाकरण सप्ताह 2.0 के तहत होलीक्रॉस एवं मोंटफोर्ट स्कूल में छात्राओं का टीकाकरण....

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 46 छात्राओं को लगाया गया एचपीवी टीका

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) संक्रमण से बचाव एवं गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की रोकथाम के उद्देश्य से जिले में 03 से 08 अगस्त 2026 तक एचपीवी विशेष टीकाकरण सप्ताह 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज 07 अगस्त को अंबिकापुर स्थित होलीक्रॉस स्कूल एवं मोंटफोर्ट स्कूल में विशेष एचपीवी टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया। टीकाकरण सत्र के दौरान होलीक्रॉस स्कूल में 28 तथा

मोंटफोर्ट स्कूल में 18 छात्राओं सहित कुल 46 छात्राओं को एचपीवी संक्रमण एवं इससे होने वाले गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए टीका लगाया गया। इस दौरान छात्राओं एवं विद्यालय प्रबंधन को एचपीवी टीकाकरण के महत्व, इसकी सुरक्षा एवं लाभों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान कर जागरूक किया गया। टीकाकरण सत्र को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सीपीएम डॉ. सीमा तिग्गा, डॉ. नीलिमा आनंद, डॉ. साधना मिश्रा, स्टाफ नर्स आंचल प्रिया लकड़ा, ए.एन.एम. शशि गुप्ता, शशि सिन्हा एवं पूर्णिमा, आरएचओ सागर राय एवं मुकेश कुशवाहा तथा जे.एस.ए. आकाश गुप्ता एवं अनुप का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने की टीकाकरण की अपील मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अभिभावकों एवं आमजन से अपील की है कि एचपीवी टीकाकरण के लिए निर्धारित आयु वर्ग की सभी पात्र बालिकाओं का समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं। एचपीवी टीकाकरण बालिकाओं को भविष्य में गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अभिभावकों से टीकाकरण के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही जानकारी का लाभ उठाते हुए अपनी पात्र बालिकाओं का टीकाकरण कराने का आग्रह किया है।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले तीन चालक दंडित,कोर्ट ने लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यातायात शाखा की कार्रवाई में दो कार चालक और एक स्कूटी चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। तीनों मामलों में न्यायालय ने 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इस प्रकार कुल 30 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस ने जांच के दौरान कार क्रमांक CG-15-EE-5646 के चालक अमिताभ पन्ना (26), निवासी सलयाडीह,थाना बतौली तथा कार क्रमांक JH-01-BF-5109 के चालक विशाल सोनवानी (24), निवासी सुर, थाना सीतापुर को रोका। दोनों के शराब के नशे में होने की पुष्टि ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण से हुई। इसी तरह स्कूटी क्रमांक CG-15-EH-8601 के चालक मुकेश मिंज (31), निवासी गंगापुर,थाना गांधीनगर को भी नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया।

स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर फिर सवाल, खेल शिक्षक पर स्टंप से पिटाई का आरोप

कमरे में बंद कर दो छात्रों को पीटने का आरोप,पीठ पर चोट के निशान,शिकायत के बाद शिक्षक हटाया गया

-संवाददाता-
बलरामपुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड स्थित प्रेमनगर के डीएव्ही मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल में दो छात्रों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शारीरिक दंड को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि खेल शिक्षक ने दोनों छात्रों को कमरे में बंद कर क्रिकेट के स्टंप से बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी पीठ पर गंभीर चोट के निशान बन गए। जानकारी के अनुसार, छुट्टी के बाद जब दोनों छात्र घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर उदासी और पीठ पर चोट के निशान देखकर परिजनों को

संदेह हुआ। काफी पूछताछ के बाद बच्चों ने बताया कि खेल शिक्षक ने उन्हें कमरे में बंद कर स्टंप से मारा और किसी को घटना की जानकारी देने पर गंभीर मामले में फंसाने की धमकी भी दी। परिजनों का कहना है कि बच्चों से यदि कोई गलती हुई थी तो इसकी जानकारी उन्हें दी जानी चाहिए थी। अनुशासन के नाम पर इस तरह का शारीरिक दंड और डराना-धमकाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने स्कूल प्रबंधन, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मामला सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने संबंधित खेल शिक्षक को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। शिक्षा विभाग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कई स्कूल पिछले एक वर्ष में अलग-अलग विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। शिक्षकों के अनुचित व्यवहार, लापरवाही और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के मामलों में कार्रवाई भी हुई है, लेकिन ताजा घटना ने यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था कितनी प्रभावी है।

CMYK

जेल,बर्खास्तगी और फिर 7.7 एकड़ जमीन! आखिर कहां से आई बढ़ती संपत्ति,कौन करेगा निष्पक्ष जांच?

एफआईआर से संयुक्त भूमि तकः सहकारिता तंत्र पर उठे नए सवाल,क्या होगी निष्पक्ष जांच?

धान शॉर्टेज,एफआईआर, बर्खास्तगी और फिर नई संपतियां...आखिर जवाबदेह कौन?

सोनपुर से 7.7 एकड़ जमीन तकः दस्तावेज़ों ने उठाए कई सवाल, जांच की मांग तेज...

सेवा समाप्ति के बाद बढ़ती संपतियों पर सवाल,क्या सहकारिता तंत्र देगा जवाब?

मैयाथान सहकारिता का दूसरा अध्यायः एफआईआर,बर्खास्तगी और फिर संयुक्त भूमि रिकॉर्ड

धान खरीदी से जमीन तक : क्या पूरे मामले की होगी स्वतंत्र जांच?

एफआईआर के बाद जमीन,गाड़ी और पुनर्बहाली की चर्चाएं...सूरजपुर सहकारिता पर फिर उठे सवाल...

सोनपुर,शिवप्रसादनगर और मैयाथान शाखा से जुड़े मामलों में दस्तावेज़ों के साथ उठे कई नए सवाल, अब निष्पक्ष जांच की मांग तेज

ओंकार पाण्डेय

सूरजपुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

भाग-1 में हमने पशुपालन ऋण वितरण, एफआईआर,सेवा समाप्ति और न्यायालयीन कार्यवाही का क्रम सामने रखा था,अब भाग-2 में सवाल उन घटनाओं पर है जो उसके बाद सामने आई,राजस्व रिकॉर्ड,सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीरें,धान खरीदी में सामने आए विवाद और विभागीय कार्रवाई के बाद भी लगातार उठते सवाल यह संकेत देते हैं कि पूरा मामला केवल एक कर्मचारी तक सीमित नहीं है,यदि इन सभी तथ्यों की निष्पक्ष जांच हो,तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि सहकारिता तंत्र में वास्तव में क्या हुआ और क्या नहीं। सूरजपुर जिले की सहकारिता व्यवस्था से जुड़े विवाद अब अलग-अलग घटनाएं नहीं रह गए हैं,उपलब्ध दस्तावेज़ यह दर्शाते हैं कि विभागीय कार्रवाई,एफआईआर और न्यायालयीन प्रक्रिया हुई,वहीं राजस्व रिकॉर्ड और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अन्य अभिलेखों के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर नए प्रश्न उठे हैं,इन प्रश्नों के उत्तर केवल निष्पक्ष,पारदर्शी और व्यापक जांच से ही मिल सकते हैं।

धान शॉर्टेज के बाद क्या बदली जांच की दिशा?

वर्ष 2025 की धान खरीदी के दौरान भैयाथान शाखा के अंतर्गत संचालित कई समितियों में धान के स्टॉक को लेकर शिकायतें सामने आईं,स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए गए कि कुछ केंद्रों में रिकॉर्ड के अनुसार धान अधिक था जबकि मौके पर स्टॉक कम मिला,इसके बाद तहसीलदार,एसडीएम और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त जांच टीमों ने निरीक्षण किया,स्थानीय लोगों और कुछ विभागीय सूत्रों का दावा है कि प्रारंभिक जांच में जिन केंद्रों पर कमी दर्ज हुई,बाद की जांच में वहीं कमी पूरी दिखाई गई,इन दावों की पुष्टि किसी सार्वजनिक अंतिम जांच रिपोर्ट से नहीं होती, इसलिए इन्हें आरोप और जनचर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए,यदि जांच रिपोर्टों में वास्तव में विरोधाभास है,तो उनका सार्वजनिक परीक्षण होना चाहिए।

निलंबन हुआ,अब पुनर्बहाली की चर्चाएं

धान खरीदी सत्र के दौरान कुछ समिति प्रबंधकों और केंद्र प्रभारियों के विरुद्ध निलंबन जैसी कार्रवाई हुई,अब स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि आगामी धान खरीदी सत्र से पहले उनमें से कुछ को पुनः कार्य पर लेने की तैयारी की जा रही है,यदि ऐसा कोई आदेश जारी होता है,तो सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि क्या संबंधित व्यक्तियों को विभागीय जांच में क्लीन चिट मिली? क्या पूर्व जांच रिपोर्ट निरस्त की गई? या फिर किसी अन्य आधार पर पुनर्बहाली का निर्णय लिया गया? इन प्रश्नों का उत्तर केवल विभागीय आदेश ही दे सकता है।

साधना कुशवाहा प्रकरण के बाद नया सवाल-संयुक्त नाम से भूमि

उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड में हदीश मोहम्मद और साधना कुशवाहा के नाम से संयुक्त कृषि भूमि दर्ज दिखाई देती है,रिकॉर्ड में अनेक खसरा नंबर और कुल लगभग 7.7 एकड़ (करीब 3.13 हेक्टेयर) भूमि का उल्लेख है,भूमि रिकॉर्ड अपने-आप में केवल स्वामित्व का रिकॉर्ड है,इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि भूमि किस वर्ष खरीदी गई,किस कीमत पर खरीदी गई या धन का स्रोत क्या था,लेकिन यह भी तथ्य है कि इससे पहले पशुपालन ऋण प्रकरण में एफआईआर, न्यायालयीन कार्यवाही और विभागीय सेवा समाप्ति जैसे घटनाक्रम हो चुके थे,ऐसे में स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि यदि किसी प्रकार का संदेह है तो सक्षम एजेंसियां भूमि खरीद के वित्तीय स्रोत की जांच करें।

अप्रैल 2024 में नई Hyundai Creta की डिलीवरी-उपलब्ध सोशल मीडिया पोस्ट में अप्रैल 2024 की एक तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें साधना कुशवाहा Hyundai शोरूम में नई Hyundai Creta की डिलीवरी लेते हुए दिखाई देती हैं,यह फोटो केवल वाहन की डिलीवरी का सार्वजनिक रिकॉर्ड दर्शाती है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वाहन किस आय या किस स्रोत से खरीदा गया,लेकिन स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि यदि संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध पहले से गंभीर विभागीय और आपराधिक कार्रवाई हुई थी,तो क्या बाद में उनकी संपत्तियों और आय के स्रोत की कभी जांच हुई? यदि हुई,तो उसका परिणाम क्या रहा? यदि नहीं हुई, तो क्यों नहीं?

'व्हाइट कार्ड एंट्री' का रहस्य-स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक चर्चा जिस विषय की होती रही है,वह कथित'व्हाइट कार्ड एंट्री' है, दस्तावेज़ों के अनुसार सेवा समाप्ति का आदेश जारी हुआ था,इसके बाद यदि किसी रूप में कार्य से दोबारा जुड़ाव हुआ,तो उसका वैधानिक आधार क्या था? क्या पुनर्नियुक्ति हुई? क्या अनुबंध पर कार्य हुआ? क्या किसी अधिकारी ने विशेष अनुमति दी? क्या समिति के रिकॉर्ड में उसका उल्लेख है? इन सवालों पर अभी तक स्पष्ट सार्वजनिक दस्तावेज़ सामने नहीं आए हैं।

क्या जांच केवल कर्मचारियों तक सीमित रही?-सहकारिता व्यवस्था में ऋण स्वीकृति,धान खरीदी,स्टॉक सत्यापन,निरीक्षण और भुगतान जैसी प्रक्रियाएं कई स्तरों पर होती हैं। ऐसे में यदि किसी मामले में गंभीर अनियमितताओं की जांच हुई,तो यह प्रश्न भी उठता है कि क्या केवल कर्मचारी स्तर पर कार्रवाई पर्याप्त थी? क्या पर्यवेक्षण और निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा हुई? क्या प्रशासनिक जवाबदेही तय की गई? इन प्रश्नों का उत्तर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

स्थानीय स्तर पर किन अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठते रहे?-स्थानीय चर्चाओं और कुछ विभागीय सूत्रों के अनुसार उस समय के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठते रहे,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध दस्तावेज़ों से नहीं होती और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है,ऐसी स्थिति में किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि लगातार ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, तो विभाग के लिए पारदर्शिता के साथ स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है।

घटती घटना | कोरिया समाचार | अम्बिकापुर सोमवार 03 अगस्त 2026 | 6
भाग-1
पशुपालन ऋण से धान शॉर्टेज तक: सहकारिता तंत्र का खेल या संरक्षण का मेल?
एफआईआर, सेवा समाप्ति, धान खरीदी में कमी और 7.7 एकड़ संयुक्त भूमि ने खड़े किए कई गंभीर सवाल, दस्तावेजों के आधार पर उठी निष्पक्ष जांच की मांग
जेल,बर्खास्तगी और फिर 7.7 एकड़ जमीन! सहकारिता तंत्र में कौन देता रहा संरक्षण?
पशुपालन ऋण से धान शॉर्टेज तक आखिर किसके संरक्षण में फलता-फूलता रहा सहकारिता का खेल?
एफआईआर,बर्खास्तगी,फिर बढ़ती संपत्ति! भैयाथान की समितियों पर आखिर किसका था संरक्षण?

क्यों जरूरी है स्वतंत्र जांच?

इस पूरे घटनाक्रम में अब कई परतें हैं पशुपालन ऋण वितरण,एफआईआर, न्यायालयीन कार्यवाही,सेवा समाप्ति,धान शॉर्टेज,विरोधाभासी जांच की चर्चाएं, संयुक्त भूमि रिकॉर्ड, वाहन की सार्वजनिक डिलीवरी, पुनर्बहाली की चर्चाएं,इन सभी को अलग-अलग देखने से पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं होती। यदि किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा समग्र जांच की जाए,तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या सभी प्रक्रियाएं नियमों के अनुरूप थीं या कहीं कोई चूक हुई।

आज भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं...

- क्या पशुपालन ऋण प्रकरण में शासन को हुई कथित आर्थिक क्षति की पूरी वसूली हुई?
- क्या धान शॉर्टेज से जुड़े सभी मामलों में अंतिम कार्रवाई पूरी हो गई?
- क्या सेवा समाप्ति के बाद कथित पुनर्बहाली का कोई वैध आदेश है?
- क्या भूमि और वाहन खरीद के वित्तीय स्रोत की किसी एजेंसी ने जांच की?
- क्या सभी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएंगी?
- क्या जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों तक सीमित रही या पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय हुई?

पत्नी ने साथ चलने से किया इनकार,तो पति ने ब्लेड से रेत दिया गला,कुदरगढ़ पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

मायके में रह रही पत्नी पर किया जानलेवा हमला,गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर,घटना में प्रयुक्त ब्लेड जब्त

-संवाददाता-
कोरिया,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिले के कुदरगढ़ चौकी क्षेत्र में पति-पत्नी के विवाद ने उस समय खूनी रूप ले लिया,जब पत्नी के साथ घर चलने से इनकार करने पर पति ने धारदार ब्लेड से उसकी गर्दन पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को पहले ओड़गी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया,जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 6 अगस्त 2026 को ग्राम भंवरखोह तेलईडांड निवासी हरदयाल सिंह ने चौकी कुदरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भांजी आहता करीब एक माह से अपने सात वर्षीय पुत्र के साथ उसके घर रह रही थी, गुरुवार सुबह करीब 9 बजे उसका पति नकुल सिंह निवासी ग्राम करीं उसके घर पहुंचा और पत्नी से अपने साथ घर चलने को कहा,बताया गया कि पत्नी ने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इससे आरोपी अत्यधिक आक्रोशित हो गया और पहले जान से मारने की धमकी दी,फिर अपने पास रखे धारदार ब्लेड से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया,ब्लेड से सामने की ओर गला काट दिए जाने से महिला गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गई,घटना के बाद परिजनों ने तत्काल 108 एंबुलेंस की सहायता से घायल महिला को ओड़गी अस्पताल पहुंचाया,वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर कर दिया।

धारा 109(1) बीएनएस के तहत दर्ज हुआ मामला- प्रार्थी की रिपोर्ट पर चौकी कुदरगढ़ पुलिस ने आरोपी नकुल सिंह आयाम (36 वर्ष) निवासी ग्राम करीं पटेलपारा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 55/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

एसपी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई-घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए,निर्देश के बाद चौकी कुदरगढ़ पुलिस ने एफएसएल क्राइम यूनिट की विशेषज्ञ डॉ. रसलीन कौर की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए और घटना में प्रयुक्त धारदार ब्लेड को जब्त कर लिया, इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी नकुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म-पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपनी पत्नी को लेने उसके मामा के घर गया था,पत्नी द्वारा साथ चलने से इनकार किए जाने पर वह गुस्से में आ गया और जान से मारने की धमकी देते हुए ब्लेड से उसकी गर्दन पर हमला कर दिया, पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

इन अधिकारियों की रही भूमिका-पूरे मामले की कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन एवं एसडीओपी ओड़गी राजेंद्र मंडावी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी संजय यादव के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक क्रांति सिंह तथा आरक्षक अमरेंद्र दुबे,मिलन सिंह, आलम साय,नरसिंह यादव एवं अनार सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अच्छा और बड़ा सोचो,लक्ष्य हासिल करने के लिए जुनून जरूरी : कलेक्टर रोक्तिमा यादव

कला,कौशल और तकनीक के समन्वय से विद्यार्थियों का भविष्य होगा उज्ज्वल

-संवाददाता-
कोरिया,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए बड़ा सपना देखना और उसे पूरा करने का जुनून होना सबसे जरूरी है, उन्होंने छात्राओं से कहा कि लक्ष्य तय करें, नियमित अध्ययन करें और अपने शिक्षकों से निरंतर मार्गदर्शन लेते रहें,मेहनत और लगन से हर मंजिल हासिल की जा सकती है,शुक्रवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पटना में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),सेवा केंद्र नया रायपुर द्वारा आयोजित प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंची कलेक्टर ने छात्राओं से आत्मीय संवाद किया तथा उनके द्वारा तैयार हस्तशिल्प उत्पादों का अवलोकन किया। उन्होंने बांस शिल्प,वुडन आर्ट,पैरा आर्ट एवं पारंपरिक गोदना पेंटिंग की सराहना करते हुए कहा कि हर बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। जरूरत केवल उसे पहचानने,निखारने और उचित मंच उपलब्ध कराने की है।

कैरियर को लेकर किया संवाद, प्राचार्य को दिए काउंसिलिंग के निर्देश-कलेक्टर ने बारहवीं की छात्राओं से उनके भविष्य के लक्ष्य पूछे। छात्राओं ने डॉक्टर, इंजीनियर,शिक्षक,पुलिस अधिकारी और वकील बनने की इच्छा जताई,इस पर उन्होंने कहा कि केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके अनुरूप अभी से तैयारी करना भी आवश्यक है,उन्होंने प्राचार्य को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की रुचि और क्षमता के अनुसार समय-समय पर उनका मार्गदर्शन एवं काउंसिलिंग सुनिश्चित करें।

प्रतिभाओं की सराहना,छात्राओं का बढ़ाया उत्साह-कलेक्टर ने छात्राओं से नृत्य एवं संगीत में रुचि के बारे में भी चर्चा की, कक्षा सातवीं की छात्रा कुमारी दीपिका सोनवानी ने मधुर गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया,छात्राओं ने कलेक्टर का आकर्षक चित्र भेंट किया,सरगुजा की प्रसिद्ध गोदना पेंटिंग कलाकार श्रीमती सफायन पावले ने कोसा शॉल पर निर्मित पारंपरिक गोदना कला की उत्कृष्ट कृति भेंट की, जबकि जशपुर के शिल्पकारों ने बांस एवं छीन से निर्मित हस्तशिल्प सामग्री भेंट की।

छात्राओं ने सीखी वुडन-बंबू आर्ट, कलेक्टर ने बढ़ाया आत्मविश्वास-जशपुर और सरगुजा से आए कारीगरों ने छात्राओं को वुडन आर्ट एवं बंबू आर्ट की तकनीक, निर्माण प्रक्रिया और शिल्प की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया,कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने वुडन-बंबू आर्ट सीखने वाले छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। छात्राओं ने बताया कि इस प्रशिक्षण से उन्हें पारंपरिक हस्तशिल्प के साथ स्वरोजगार की नई संभावनाओं की जानकारी मिली है।

डिजिटल लर्निंग लैब में एआर-वीआरतकनीक का लिया अनुभव-कलेक्टर ने विद्यालय में संचालित 'मिशन कामयाबी' के अंतर्गत विकसित डिजिटल लर्निंग लैब का अवलोकन किया तथा एआर (ऑगमेंटेड रियलिटी), वी आर (वर्चुअल रियलिटी),एक्सपीरिएंशियल लर्निंग और आधुनिक शिक्षण तकनीकों का स्वयं अनुभव किया,उन्होंने कहा कि अब शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहेगी। आधुनिक तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी विज्ञान, गणित,इतिहास एवं अन्य विषयों को देखकर, समझकर और स्वयं करके सीख सकेंगे, इससे विद्यार्थियों में रचनात्मकता,नवाचार, समस्या-समाधान क्षमता तथा 21वीं सदी के आवश्यक कौशल विकसित होंगे,कलेक्टर ने प्रशिक्षण दे रहे शिक्षक से कहा...बहुत ही गम्भीरता से इस पर ध्यान दें ताकि हमारे बच्चे इन विषयों पर ज्यादा रूचि लेकर आगे बढ़ें।

हुनर और तकनीक का संगम बनाएगा आत्मनिर्भर पीढ़ी-कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने कहा कि पारंपरिक कला,आधुनिक तकनीक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समन्वय विद्यार्थियों को आत्म विश्वासी,रोजगारोन्मुख और आत्मनिर्भर बनाएगा,उन्होंने कहा कि स्कूलों में ऐसे नवाचार बच्चों के सपनों को नई उड़ान देंगे और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे,इसके पहले छात्राओं ने कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव का टीका लगाकर स्वागत किया।

CMYK

सीएम हेल्पलाइन 1076 में भ्रष्टाचार की जांच की शिकायत

24 घंटे के भीतर 'संबंधित नहीं' बताकर हटाई गई जिम्मेदारी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्ति-पदोन्नति में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग करने वाली शिकायत पर कार्रवाई के बजाय बदलती रही स्थिति

राजधानी विशेष

रायपुर,06 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई थी कि आम नागरिक बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए घर बैठे अपनी शिकायत शासन तक पहुंचा सकें और उसका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण हो,सरकार स्वयं समय-समय पर अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर यह संदेश देती रही है कि शिकायतों को केवल पोर्टल पर बंद करना उद्देश्य नहीं है,बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान करना ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की मूल भावना है, लेकिन जब इसी व्यवस्था की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को परखने के लिए दैनिक घटती-घटना ने एक गंभीर जनहित का मामला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज कराया,तो शिकायत के साथ जो हुआ उसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रयोग के तौर पर दर्ज कराई गई शिकायत

दैनिक घटती-घटना ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 की कार्यप्रणाली को समझने और उसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करने के उद्देश्य से 3 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत क्रमांक WP260800133102 दर्ज कराई, शिकायत सफलतापूर्वक स्वीकार की गई और पोर्टल पर'Complaint Registered Successfully'का संदेश भी प्रदर्शित हुआ, इसके बाद शिकायत प्रक्रिया में चली गई।

क्या था शिकायत का विषय?

यह कोई व्यक्तिगत विवाद या निजी समस्या नहीं थी,बल्कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर हुई नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में कथित अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच की मांग थी,शिकायत में आरोप लगाया गया कि विभाग में कई वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित Food Safety and Standards Rules,2011 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां की गईं, शिकायत में यह भी मांग की गई कि वर्ष 2011 से अब तक हुई सभी नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों की स्वतंत्र जांच कराई जाए, अधिकारियों की शैक्षणिक पात्रता का सत्यापन कराया जाए तथा स्थापना शाखा की भूमिका की भी जांच हो,शिकायत में यह भी अनुरोध किया गया कि यदि प्रथम दृष्टया अनियमितता प्रतीत होती है तो पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू,एसीबी अथवा किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए तथा जांच पूरी होने तक प्रस्तावित पदोन्नतियों पर रोक लगाने पर विचार किया जाए।

24 घंटे बाद बदल गई शिकायत की स्थिति-शिकायत 3 अगस्त को दर्ज हुई, उसी दिन उसकी स्थिति'खुला' दिखाई गई, इसके बाद शिकायत निराकरण अधिकारी (एल-1) को भेजे जाने की जानकारी पोर्टल पर दर्ज हुई, लेकिन अगले ही दिन यानी 4 अगस्त को शिकायत की स्थिति बदलकर'संबंधित नहीं' कर दी गई,पोर्टल पर दर्ज टिप्पणी में लिखा गया शिकायत वर्तमान में संबंधित विभाग/अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है,इसके बाद दूसरी टिप्पणी दर्ज हुई शिकायत संबंधित विभाग/अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अतः इसे यथोचित उचित प्राधिकारी को पुनः भेजा जा रहा है,लेकिन इसके बाद शिकायतकर्ता को यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई कि शिकायत वास्तव में किस विभाग को भेजी गई, किस अधिकारी को हस्तांतरित हुई और आगे उसकी जांच किस स्तर पर होगी।

सबसे बड़ा सवाल—यदि संबंधित नहीं थी तो स्वीकार क्यों की गई?-यह पूरा घटनाक्रम कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े करता है यदि शिकायत संबंधित विभाग की नहीं थी तो पोर्टल ने उसे स्वीकार क्यों किया? यदि शिकायत गलत विभाग में चली गई थी तो उसे किस विभाग को भेजा गया? क्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज जनहित की शिकायतों की जांच केवल तकनीकी आधार पर समाप्त की जा सकती है? क्या शिकायतकर्ता को यह जानने का अधिकार नहीं कि उसकी शिकायत अब किस अधिकारी के पास लंबित है? यदि शिकायत में भ्रष्टाचार, नियमों के उल्लंघन और अपात्र नियुक्तियों जैसे गंभीर आरोप हों तो क्या केवल'संबंधित नहीं' लिख देना पर्याप्त जवाब माना जा सकता है?

जनहित से जुड़ा है पूरा मामला-खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसा पद है जो सीधे जनता के स्वास्थ्य,खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता,मिलावट की रोकथाम और खाद्य सुरक्षा कानूनों के पालन से जुड़ा है,यदि इस पद पर नियुक्ति या पदोन्नति में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसका प्रभाव केवल विभाग तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा,इसी कारण शिकायत में उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

सरकार का दावा और हकीकत

दिलचस्प बात यह है कि शिकायत दर्ज होने के ठीक कुछ दिन बाद ही प्रदेशभर के अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन और गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि शिकायत का उद्देश्य केवल पोर्टल पर जवाब देना नहीं है,शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान करना अनिवार्य है,आवश्यकता पड़ने पर स्थल निरीक्षण,तथ्यात्मक जांच और दस्तावेज अपलोड किए जाएं,यदि शिकायत संबंधित विभाग की नहीं है तो उसे उचित विभाग को तत्काल स्थानांतरित किया जाए,यानी शासन स्वयं अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निराकरण का प्रशिक्षण दे रहा है,लेकिन उसी व्यवस्था में दर्ज एक जनहित की शिकायत के साथ जो हुआ,वह अलग कहानी बयान करता है।

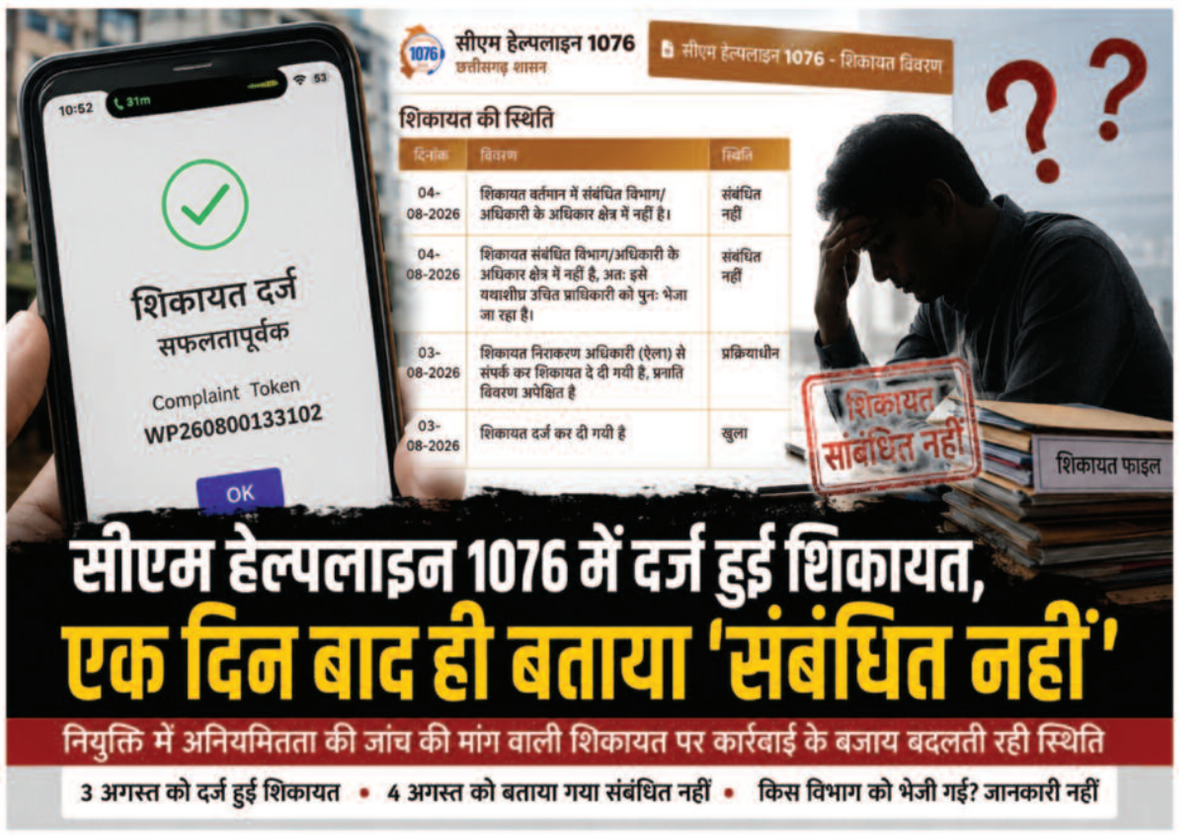

सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज हुई शिकायत, एक दिन बाद ही बताया 'संबंधित नहीं'

नियुक्ति में अनियमितता की जांच की मांग वाली शिकायत पर कार्रवाई के बजाय बदलती रही स्थिति

3 अगस्त को दर्ज हुई शिकायत • 4 अगस्त को बताया गया संबंधित नहीं • किस विभाग को भेजी गई? जानकारी नहीं

क्या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने का मंच बनकर रह गई है?

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल का उद्देश्य जनता और शासन के बीच विश्वास का पुल बनना है,यदि शिकायत दर्ज होने के बाद बिना स्पष्ट कारण बताए उसे 'संबंधित नहीं' कहकर आगे बढ़ा दिया जाए या उसकी स्थिति अस्पष्ट छोड़ दी जाए,तो इससे शिकायतकर्ता का विश्वास प्रभावित होना स्वाभाविक है, विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी शिकायत निवारण प्रणाली की सफलता शिकायतों की संख्या से नहीं,बल्कि उनके पारदर्शी, कारणयुक्त और गुणवत्तापूर्ण निराकरण से मापी जाती है।

अब इन सवालों के जवाब का इंतजार

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या शिकायत वास्तव में किसी सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई है? क्या इसकी स्वतंत्र जांच होगी? क्या शिकायतकर्ता को विभाग बदलने और आगे की कार्रवाई की सूचना दी जाएगी? या फिर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में दर्ज यह शिकायत भी 'संबंधित नहीं'की टिप्पणी के साथ फाइलों में सिमटकर रह जाएगी? यह मामला केवल एक शिकायत का नहीं,बल्कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल की विश्वसनीयता,पारदर्शिता और शिकायत निवारण प्रणाली की वास्तविक कार्यप्रणाली की भी परीक्षा बन गया है।

कोरिया में कांग्रेस को झटका,मुस्लिम समुदाय के युवा अफरोज खान भाजपा में शामिल

पटना क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता ने ग्रहण की भाजपा की प्राथमिक सदस्यता, भाजपा ने इसे संगठन विस्तार और बढ़ते जनसमर्थन का संकेत बताया

-संवाददाता-

कोरिया,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के पटना क्षेत्र की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता अफरोज खान ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली,भाजपा मंडल अध्यक्ष रामलखन यादव ने इसकी जानकारी सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की,इसके बाद एक अन्य मुस्लिम समुदाय के युवा के भी भाजपा की सदस्यता लेने की जानकारी सामने आई, राजनीतिक दृष्टि से अफरोज खान का भाजपा में शामिल होना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे मुस्लिम समुदाय से आते हैं,भाजपा नेताओं का कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति का दल परिवर्तन नहीं,बल्कि पार्टी की नीतियों और कार्यशैली के प्रति बढ़ते विश्वास का संकेत है। भाजपा मंडल अध्यक्ष रामलखन यादव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा संगठन की कार्यशैली से प्रभावित होकर विभिन्न वर्गों के लोग लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अब मुस्लिम समुदाय के युवाओं में भी भाजपा के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो रही है,अफरोज खान के भाजपा में शामिल होने के बाद क्षेत्र में इस बात की भी चर्चा है कि आने वाले समय में मुस्लिम समुदाय के कुछ अन्य युवा भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं,हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है,राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि विभिन्न सामाजिक वर्गों से जुड़े लोगों का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है तो इसका असर आगामी चुनावों और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है,वहीं कांग्रेस की ओर से इस घटनाक्रम पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है,ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इस राजनीतिक बदलाव को किस तरह लेती है और संगठन स्तर पर क्या रणनीति अपनाती है,अफरोज खान के भाजपा प्रवेश को भाजपा संगठन अपने जनाधार के विस्तार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, जबकि राजनीतिक जानकार इसे कोरिया जिले की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के संकेत के रूप में भी देख रहे हैं।

दुष्कर्म एवं एसटी-एससी अत्याचार मामले में दोषी को 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

विशेष न्यायालय बैकुंठपुर का फैसला,पीड़िता के घर में घुसकर किया था दुष्कर्म,बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट के तहत हुई सजा

-संवाददाता-

बैकुंठपुर/कोरिया,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विशेष न्यायालय, बैकुंठपुर के विशेष न्यायाधीश आशीष पाठक ने दुष्कर्म एवं एससी-एसटी अत्याचार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी नामेन्द्र दास को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 31 जुलाई 2026 को विशेष आपराधिक प्रकरण क्रमांक 03/2026 में यह निर्णय पारित किया। न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन के अनुसार, 28 नवंबर 2025 की रात लगभग 11 बजे बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के जुनापारा स्थित किराये के मकान में,जहां पीड़िता निवास करती थी, आरोपी नामेन्द्र दास जबरन घर में घुस गया और पीड़िता के साथ बलपूर्वक दुष्कर्म किया। पीड़िता अनुसूचित जनजाति (गोंड) वर्ग से संबंधित है तथा आरोपी इस वर्ग का सदस्य नहीं है। इसके बावजूद आरोपी ने उसकी जातीय स्थिति की जानकारी होने के बाद भी अपराध को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर थाना अजाक बैकुंठपुर में अपराध क्रमांक 12/2025 दर्ज कर मामले की विवेचना की गई, सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(1) के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 331(4) के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

सूरजपुर में एमपावर इंटरस्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ....

उद्घाटन मुकाबले में रिवरडेल वर्ल्ड स्कूल,गोंदिया ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया ग्लोबल स्कूल,रायपुर को 3-1 से हराया

मेहनत,अनुशासन और खेल भावना ही सफलता की असली पहचान : एसपी योगेश पटेल

-संवाददाता-

सूरजपुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

साधु राम विद्या मंदिर,सूरजपुर द्वारा आयोजित एमपावर इंटरस्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ, विद्यालय परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह में जिले के पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए,खेलों के प्रति विद्यार्थियों में उत्साह, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित इस तीन दिवसीय टूर्नामेंट की शुरुआत खिलाड़ियों के परिचय, ध्वजारोहण,दीप प्रज्ज्वलन एवं अतिथियों के स्वागत के साथ हुई। समारोह में खिलाड़ियों ने खेल भावना,अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन का संकल्प लिया। विद्यालय परिसर में उत्साहपूर्ण माहौल के बीच विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ियों ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिता का आगाज किया,मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि मेहनत,अनुशासन और खेल भावना जीवन में आगे बढ़ने का सबसे सशक्त माध्यम है,उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक फिटनेस तक सीमित नहीं हैं,बल्कि यह नेतृत्व क्षमता, टीम भावना,आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने का भी प्रभावी माध्यम हैं, उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में हार से कभी घबराना नहीं चाहिए और जीत पर अहंकार नहीं करना चाहिए,सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं,एसपी पटेल ने अपने छात्र जीवन और यूपीएससी परीक्षा की तैयारी से जुड़े अनुभव भी विद्यार्थियों के साथ साझा किए,उन्होंने कहा कि स्कूली जीवन में नकारात्मक सोच से दूर रहकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए,उन्होंने सभी प्रतिभागी टीमों को उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं,कार्यक्रम में एमपावर के डायरेक्टर गोविंद मुदलियार,एचआर सुश्री निधि, साधु राम विद्या मंदिर के डायरेक्टर डॉ. राहुल अग्रवाल,एसएमसी अध्यक्ष सुनील अग्रवाल,पूर्व पार्षद संजय डोसी, विद्यालय की प्राचार्या खुशबू सिंह तथा उप-प्राचार्य दीन दयाल तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे,कार्यक्रम का संचालन तुलेश्वर राजवाड़े,दीपक पटले और निदा फ़ाजली ने किया,विद्यालय परिवार ने सभी अतिथियों का स्वागत कर स्मृति चिह्न भेंट किए, टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला कोलंबिया ग्लोबल स्कूल,रायपुर और रिवरडेल वर्ल्ड स्कूल,गोंदिया के बीच खेला गया, दोनों टीमों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया और निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी पर रहा,इसके बाद मैच का निर्णय पेनल्टी शूटआउट से किया गया, जिसमें रिवरडेल वर्ल्ड स्कूल,गोंदिया ने 3-1 से जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत की, उद्घाटन समारोह में विद्यालय परिवार,विभिन्न प्रतिभागी विद्यालयों के शिक्षक,प्रशिक्षक,अभिभावक एवं बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे,पूरे आयोजन में उत्साह, अनुशासन और खेल भावना का उत्कृष्ट वातावरण देखने को मिला,यह इंटरस्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट तीन दिनों तक चलेगा, जबकि इसका फाइनल मुकाबला एवं समापन समारोह 8 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने उम्मीद जताई कि प्रतियोगिता से विद्यार्थियों में खेल प्रतिभा निखरेगी और उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा।

मुफ्त सफर नहीं मिला तो निजी सुरक्षा गार्ड ने बीच रास्ते रुकवाई स्कूल बस,चालक पर बंदूक तानकर की मारपीट

बाइक से पीछा कर काली मंदिर के पास रोकी बस,छात्र-छात्राओं के सामने की वारदात का वीडियो वायरल,पुलिस ने दर्ज किया मामला

-संवाददाता-

सूरजपुर,07 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

जिले के बिश्रामपुर क्षेत्र में एसईसीएल द्वारा अनुबंधित स्कूल बस में मुफ्त यात्रा नहीं मिलने से नाराज एक निजी सुरक्षा गार्ड ने फिल्मी अंदाज में बस का पीछा कर उसे बीच रास्ते रुकवा लिया,इसके बाद बस में चढ़कर चालक पर बंदूक तान दी और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना के समय बस में कॉलेज के छात्र-छात्राएं सवार थे,जिन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा,वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है,पुलिस ने बस चालक की शिकायत पर आरोपी गार्ड के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रास्ते में बस रोकने का किया इशारा-पुलिस के अनुसार, 3 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे एसईसीएल अनुबंधित स्कूल बस कॉलेज के छात्र-छात्राओं को लेकर बिश्रामपुर से अंबिकापुर जा रही थी, इसी दौरान आरटीआई कॉलोनी निवासी निजी सुरक्षा गार्ड मंगला यादव ने बस को रोकने का इशारा किया,बस चालक रविंद्र पासवान ने बस नहीं रोकी,चालक ने बताया कि यह छात्रों के परिवहन के लिए निर्धारित स्कूल बस है और नियमों के अनुसार बीच रास्ते किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बैठाया जा सकता।

बाइक से पीछा कर बीच रास्ते रुकवाई बस-बस नहीं रुकने से नाराज सुरक्षा गार्ड ने एक राहगीर की बाइक पर बैठकर बस का पीछा शुरू कर दिया,कुछ दूरी पर भटगांव मार्ग स्थित काली मंदिर के पास उसने बस को रुकवा लिया,बस रुकते ही आरोपी उसमें चढ़ गया और चालक से बहस शुरू कर दी,चालक द्वारा दोबारा नियमों का हवाला देने पर गार्ड ने कथित तौर पर अपना आपा खो दिया।

चालक पर तानी बंदूक, फिर की मारपीट-प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गार्ड ने चालक पर बंदूक तान दी और गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी,अचानक हुई इस घटना से बस में बैठे छात्र-छात्राओं में अफरा-तफरी मच गई,बस में मौजूद छात्राएं डर के कारण सहम गईं और चालक को बचाने की गुहार लगाने लगीं,वहीं कुछ छात्रों ने हिम्मत दिखाते हुए बीच-बचाव किया, इसी दौरान जिस बाइक पर बैठकर आरोपी बस तक पहुंचा था,उस बाइक चालक ने भी हस्तक्षेप किया और आरोपी के हाथ से बंदूक छीनकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया।

छात्रों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल-घटना के दौरान बस में मौजूद कुछ छात्रों ने अपने मोबाइल फोन से पूरी वारदात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर लोगों में सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन में हथियार के साथ इस तरह की हरकत पर सवाल उठने लगे हैं।

बस चालक ने दर्ज कराई शिकायत-घटना के बाद बस चालक रविंद्र पासवान ने पूरे मामले की जानकारी एसईसीएल प्रबंधन को दी और बिश्रामपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी निजी सुरक्षा गार्ड मंगला यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 30 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 115 (2),126(2), 296 (बी) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल-यह घटना केवल मारपीट का मामला नहीं बल्कि छात्रों की सुरक्षा से भी जुड़ा गंभीर विषय बन गई है,जिस बस में कॉलेज के छात्र-छात्राएं सफर कर रहे थे,उसी बस में हथियार लेकर चढ़ जाना और चालक के साथ मारपीट करना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है,अब पुलिस वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

नयनतारा और कविन स्टारर फिल्म हीईई...अब 28 अगस्त को रिलीज

डायरेक्टर विष्णु एडवन की बहुप्रतीक्षित रोमांटिक एंटरटेनर फिल्म हीईई..जिसमें नयनतारा और कविन मुख्य भूमिकाओं में हैं-के मेकर्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि यह फिल्म अब इस साल 28 अगस्त को दुनिया भर में रिलीज होगी। फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले प्रोडक्शन हाउस में से एक, सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह घोषणा की। उन्होंने लिखा, हम जानते हैं कि आप हीईई..) कहने का इंतज़ार कर रहे थे और अब आप आखिरकार ऐसा कर सकते हैं! अपने कैलेंडर में 28 अगस्त की तारीख मार्क कर लें क्योंकि इस सीज़न की सबसे दिल को छू लेने वाली एंटरटेनर फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि यह फिल्म मूल रूप से 14 अगस्त को रिलीज़ होने वाली थी। हालाँकि,अब मेकर्स ने फिल्म को 28 अगस्त को रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है। याद दिला दें कि सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म को यू/ए सर्टिफ़िकेट के साथ रिलीज़ के लिए मंज़ूरी दे दी है। ज़ी स्टूडियोज़ साउथ,द राउडी पिक्चर्स और सेवन स्क्रीन स्टूडियोज़ द्वारा संयुक्त रूप से प्रोड्यूस की जा रही इस फिल्म में के. भाग्यराज,प्रभु,राधिका,सत्यन,आदित्य कथिर और कुरेशी सहित कई कलाकार नज़र आएँगे।

फिल्म की यूनिट से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि फिल्म की कहानी तीन शहरों-चेन्नई, कोयंबटूर और पोलाची - में सेट है। उन्होंने यह भी बताया कि यह फिल्म एक फ़ैमिली एंटरटेनर होगी और इसमें कोई विलेन नहीं होगा। विष्णु एडवन,जो इस फिल्म से डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं,इससे पहले मशहूर डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ कई प्रोजेक्ट्स में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं, जिनमें कैथी, मास्टर और विक्रम शामिल हैं।

डायरेक्टर विष्णु एडवन ने पहले अपनी फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि यह एक बेहतरीन फ़ैमिली एंटरटेनर होगी जो सच्चे प्यार के बारे में बात करेगी। फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि यह पहली बार होगा जब नयनतारा और कविन एक साथ काम कर रहे हैं। मज़बूत टेक्निकल टीम वाली इस फिल्म में म्यूज़िक जेन मार्टिन का होगा और सिनेमैटोग्राफ़ी राजेश शुक्ला करेंगे। फ़िल्म की एडिटिंग काबिल फ़िलोमिन राज करेंगे और आर्ट डायरेक्शन शेखर बी. करेंगे। फ़िल्म में डांस की कोरियोग्राफ़ी ब्रिंदा करेंगी,जबकि स्टंट की कोरियोग्राफ़ी दिनेश कासी करेंगे।

हर्षवर्धन-संजीदा की डेटिंग की चर्चा तेज

बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के कलाकार हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। दोनों के गुपचुप तरीके से डेट करने की खबरें सामने आ रही हैं।

हालांकि,हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख ने अब तक इन खबरों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोनों ने न तो इन अटकलों की पुष्टि की है और न ही इनका खंडन किया है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर दोनों के प्रशंसक उनकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ फैंस ने दोनों की हालिया तस्वीरों और पोस्ट में समानताएं नोटिस की हैं, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख के रिश्ते को लेकर चर्चा तब शुरू हुई जब फैंस ने उनकी कुछ सफारी तस्वीरों में समानताएं देखीं। प्रशंसकों ने दावा किया कि दोनों ने अलग-अलग पोस्ट में एक जैसी जगहों और माहौल की तस्वीरें साझा की थीं। हालांकि,दोनों कलाकारों की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स उनकी पोस्ट को जोड़कर कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। हर्षवर्धन की मॉनसून छुट्टियों की तस्वीरें चर्चा में करीब एक सप्ताह पहले हर्षवर्धन राणे ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें साझा की थीं,जिनमें उन्होंने अपनी मॉनसून छुट्टियों की झलक दिखाई थी। उन्होंने बताया कि वह पुणे के पानशेत स्थित 'विन ओवर वाटर्स' में समय बिता रहे थे। तस्वीरों में वह प्राकृतिक माहौल का आनंद लेते नजर आए। उन्होंने पोर्टेबल स्टोव पर खुद खाना बनाया, हरियाली के बीच चाय का लुत्फ उठाया और जंगल के बीच बने आरामदायक केबिन में समय बिताया।

हर्षवर्धन की इन तस्वीरों में प्रकृति के करीब बिताए गए शांत पलों की झलक देखने को मिली। उनके प्रशंसकों ने इन तस्वीरों को काफी पसंद किया और कमेंट्स के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी। संजीदा की पोस्ट से भी मिली समान झलक हर्षवर्धन की छुट्टियों वाली तस्वीरों के बाद फैंस ने संजीदा शेख की हालिया पोस्ट में भी कुछ समानताएं देखने का दावा किया। सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों के पोस्ट में स्थान, माहौल और तस्वीरों के अंदाज को लेकर तुलना शुरू कर दी।

कुछ प्रशंसकों का मानना है कि दोनों कलाकार एक ही जगह या आसपास के स्थानों पर समय बिता रहे थे। हालांकि,इन दावों की पुष्टि दोनों में से किसी ने नहीं की है। दोनों कलाकार निजी जिंदगी को रखते हैं निजी हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख दोनों ही अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। दोनों कलाकार सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों से जुड़े मामलों में ज्यादा जानकारी साझा नहीं करते। यही वजह है कि डेटिंग की खबरों के बावजूद दोनों की ओर से कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। हर्षवर्धन और संजीदा का करियर हर्षवर्धन राणे हिंदी फिल्मों के साथ-साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी काम कर चुके हैं। वह अपनी फिल्मों और अभिनय के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मों में रोमांटिक और एक्शन भूमिकाओं को दर्शकों ने पसंद किया है।

वहीं,संजीदा शेख टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने कई चर्चित धारावाहिकों में काम किया है और अपनी अभिनय प्रतिभा के दम पर पहचान बनाई है। फैंस की नजर सोशल मीडिया गतिविधियों पर सोशल मीडिया के दौर में कलाकारों की छोटी-छोटी गतिविधियां भी प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। हर्षवर्धन और संजीदा की पोस्ट में नजर आई कथित समानताओं ने एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि, जब तक दोनों कलाकार खुद इस बारे में कुछ नहीं कहते, तब तक ये केवल अटकलें ही मानी जाएंगी। फिलहाल, हर्षवर्धन राणे और संजीदा शेख अपने-अपने काम और निजी जीवन में व्यस्त हैं,जबकि उनके प्रशंसक दोनों की अगली पोस्ट और किसी आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं।

गौरव मेरा कंफर्ट जोन नहीं,डॉग वाले बयान पर आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी

टेलीविजन अभिनेत्री और लॉकअप-2 कंटेस्टेंट रही आकांक्षा चमोला ने पति गौरव खन्ना को लेकर दिए गए विवादित बयान पर चुप्पी तोड़ी। अभिनेत्री ने बताया कि जिस तरह से उनके बयानों को तोड़कर दिखाया गया है, वैसा कुछ भी नहीं था। आकांक्षा चमोला ने शो से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैं चाहती थी कि शो के अंदर विजिटर के तौर पर मुझसे वो लोग मिलने आए, जिनके साथ मैं अपना कंफर्ट महसूस करती हूं जैसे कि मेरे माता-पिता या फिर डॉग आते तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि इनके साथ मैं अपना कंफर्ट महसूस करती हूं। गौरव भले ही मेरा पति हैं और अब हम डिवॉर्स लेने जा रहे हैं,लेकिन वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं हैं। वो पता नहीं क्यों आया,शायद अपनी मर्जी से आया होगा। दरअसल, शो के दौरान आकांक्षा चपोला के पति गौरव खन्ना उनसे मिलने के लिए आए थे, जिसके कुछ एपिसोड बाद अभिनेत्री ने बताया था कि शो के दौरान गौरव खन्ना की जगह कोई ऐसा मिलने आता, जिसके साथ वो अपनापन महसूस करती, भले उनका डॉग मिलने आता।

शो में एंट्री लेने से पहले आकांक्षा चमोला ने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताया था कि वह और गौरव खन्ना एक साल से अलग रह रहे हैं और तलाक लेने जा रहे हैं। इसके बाद श्रेया कालरा ने उनका दूसरा सीक्रेट रिवील कर दिया था कि वे बायसेक्सुअल हैं, जिसके बाद आकांक्षा चमोला ने ये बात स्वीकारी भी थी। साथ ही ये भी बताया था कि पति गौरव खन्ना को भी उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में पता था।रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए गए इस शो में शिल्पा शिंदे,श्रेया कालरा,आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सुनीता आहूजा,राम कपूर,शिवांगी जोशी,हर्षद चोपड़ा,सूफी मोतीवाला,धीरज धूपर,माधुरी जैन ग्रोवर,रियाज अली और वरुण यादव उर्फ लैला जैसे पॉपुलर नाम थे,हालांकि कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने टॉप 3 की रेस में शिवांगी जोशी और योगेश रावत को हराकर इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर 1 करोड़ का इनाम भी अपने नाम किया।

खेल समाचार

जिम्नास्टिक्स में भारत का नया इतिहास

अरिहा पंगमबाम ने एरोबिक एशियाई चैंपियनशिप में जीता गोल्ड

एरोबिक जिम्नास्टिक्स एशियाई चैंपियनशिप में भारत के खाते में पहली बार गोल्ड मेडल आया...अरिहा पंगमबम फाइनल में 19.100 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया...

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। अरिहा पंगमबम एरोबिक जिम्नास्टिक्स एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। वह इस चैंपियनशिप के सीनियर महिला व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। भारतीय जिम्नास्ट ने फाइनल में 19.100 के स्कोर के साथ पोडियम पर शीर्ष स्थान हासिल किया और इस प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। मणिपुर की अरिहा पंगमबम ने 'आर्टिस्ट्री' के लिए 8.650, 'एक्जीक्यूशन' के लिए 7.600 और 'डिफिकल्टी' के लिए 2.850 अंक हासिल करके गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। 2026 एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप फिलीपींस में 4 से 7 अगस्त तक आयोजित की गई। भारतीय जिम्नास्टिक महासंघ के अध्यक्ष सुधीर मित्तल ने कहा, 'हमारे लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्हें और उनके कोच को बधाई।'

एसएलसी इलेवन का बड़ा स्कोर,जडेजा, सुथार और कुलदीप ने झटके 2-2 विकेट

कोलंबो,07 अगस्त 2026। शुक्रवार को कोलंबो के नॉन डेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर तीन दिन के वॉर्म-अप मैच के पहले दिन, श्रीलंका क्रिकेट इलेवन ने 90 ओवर में 8 विकेट पर 363 रन बनाए। इस दौरान भारतीय स्पिन अटैक के रवींद्र जडेजा,मानव सुथार और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए। रेगुलर कप्तान शुभमन गिल की दाहिनी रिंग फिंगर में चोट के कारण उनकी गैर-मौजूदगी में केएल राहुल ने टीम की कमान संभाली। जडेजा (2-64), सुथार (2-48) और कुलदीप (2-76) की तिकड़ी ने उस सपाट पिच से काफी टर्न हासिल किया, जिससे दिन की शुरुआत में तेज़ गेंदबाज़ों को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी। लंबे कद के तेज़ गेंदबाज़ गुरनूर बरार ने एक विकेट लिया, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को कोई विकेट नहीं मिला।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फ़ैसला करने के बाद, मेज़बान टीम को शानदार शुरुआत मिली। ओपनर निशान मदुष्का और रविंदु रसंथा ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी करके सुबह के सेशन में दबदबा बनाए रखा। मदुष्का ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार फ़ॉर्म का प्रदर्शन किया और भारतीय

तेज़ गेंदबाज़ों की गेंदों को मैदान के चारों ओर खेला, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी के कारण वह 66 रन पर रन-आउट हो गए। सिराज और कृष्णा ने ऐसी पिच पर शुरुआत में अनुशासन की कमी दिखाई, जिस पर हल्की हरी घास थी लेकिन गेंद को ज़्यादा लेटरल मूवमेंट नहीं मिल रहा था। आईपीएल 2026 के बाद पहली बार मैदान पर लौटे जडेजा ने लंच के बाद दूसरे विकेट की साझेदारी को तोड़ा; उन्होंने पसिंदु सूरियाबंदारा को एक ऐसी गेंद पर बोल्ड किया जो तेज़ी से स्किड होकर स्टंप्स से जा टकराई। इसके बाद सुथार ने अपनी फ़्लाइट और टर्न का जलवा दिखाया और रसंथा को पिच पर आगे बढ़कर लापरवाही से शॉट खेलने के लिए उकसाया, जिससे एक और खतरनाक साझेदारी टूट गई। बरार ने तेज़ गति और उछाल के साथ प्रभावशाली स्पेल डाला और चाय के ब्रेक से ठीक पहले पवन रत्नायके को आउट किया। शाम के सेशन में भारत ने खेल पर और ज़्यादा पकड़ बना ली क्योंकि पिच से स्पिनरों को मदद मिलने लगी थी। कुलदीप ने अहान विक्रमसिंघे को आउट किया; बल्लेबाज़ ने एक एम्बिशियस स्वीप शॉट खेला और गेंद टॉप-एज होकर डीप में खड़े बरार के हाथों में चली गई। इसके बाद उन्होंने अंजला बंदारा को एलबीडब्ल्यू आउट करके श्रीलंका के मिडिल-ऑर्डर की कमर तोड़ दी। कप्तान सोनल दिनुशा ने शानदार अर्धशतक लगाकर बहादुरी से जवाबी हमला किया और अपनी टीम का स्कोर 300 रन के पार पहुँचाया। लेकिन जडेजा ने वापसी करते हुए रमेश मेंडिस को सीधी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया, और फिर सुथार ने एक तेज़ आर्म बॉल से दिनुशा की 52 रन की पारी का अंत किया।

बाद में टीम में शामिल हुए ऑफ-स्पिनर सारांश जैन ने बिना किसी विकेट के लंबा स्पेल डाला। हालाँकि, श्रीलंका के खिलाफ 15 अगस्त से गाले में शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले पूरी बॉलिंग यूनिट को गेंदबाजी का अच्छा अभ्यास मिला, लेकिन प्रैक्टिस मैच के पहले ही दिन 360 से ज़्यादा रन देना उनके लिए चिंता का विषय हो सकता है। संक्षिप्त स्कोर: श्रीलंका क्रिकेट इलेवन 90 ओवर में 363/8 (रविंदु रसंथा 71, निशान मदुष्का 66; मानव सुथार 2-33, रवींद्र जडेजा 2-64) बनाम भारत।

28 अगस्त से विमेंस एशिया कप की शुरुआत

नई दिल्ली,07 अगस्त 2026। एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने शुक्रवार को विमेंस एशिया कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त से होगी। भारत और पाकिस्तान को विमेंस एशिया कप 2026 के 'ग्रूप-ए' में रखा गया है। दोनों टीमें 5 सितंबर को 'हाई-वोल्टेज मैच' में आमने-सामने होंगी।यह विमेंस एशिया कप का छठा संस्करण होगा जो टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें 8 टीमों को 2 ग्रूप में बांटा गया है। 'ग्रूप-ए' में भारत और पाकिस्तान के साथ थाईलैंड और हांगकांग (चीन) शामिल हैं, जबकि 'ग्रूप-बी' में श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई और इंडोनेशिया को रखा गया है। प्रत्येक ग्रूप की शीर्ष-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी, जिसका खिताबी मैच 13 सितंबर को आयोजित हागा। सभी मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में फ्लडलाइट्स में खेले जाएंगे।

शतरंज की दुनिया में भारत का डंका

20 साल के प्रज्ञानंद ने अमेरिका में रचा इतिहास; घर ले गए 47 लाख रुपए

सेंट लुईस,07 अगस्त 2026। भारतीय शतरंज के युवा सनसनी आर. प्रज्ञानंद ने एक बार फिर पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज़ 2026 के रोमांचक मुकाबले में उन्होंने ऐतिहासिक खिताबी जीत दर्ज की है। 20 वर्षीय इस होनहार ग्रैंडमास्टर ने पांच दिनों तक चले इस पूरे टूर्नामेंट में ऐसा दबदबा बनाया कि विरोधी खिलाड़ी उनके सामने पानी भरते नजर आए। अपनी इस जादुई जीत के साथ ही उन्होंने लाखों रुपये की इनामी राशि भी अपने नाम कर ली है।

कार्यालय नगर पंचायत लखनपुर,जिला-सरगुजा,छ0ग0

फोन नं0: 07774261501 EMAIL :- cmolakhanpur@gmail.com

क्र./1065/लो0नि0वि0/न0पं0/2026-2027 लखनपुर,दिनांक-06/08/2026

द्वितीय ई- प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

नगर पंचायत लखनपुर में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत निविदाकारों से निर्माण कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

System Tender no	Estimated Amount (Lakh)	Earnest Money Deposit	Bid Submission Start Date & Time	Bid Due Date & Time	Physical Document Submission Date & Time	Bid Open Date & Time
197013	16.92	12700/-	06/08/2026 After 17.30 PM	21/08/2026 Before 17.30 PM	25/08/2026 Before 14.00 PM	25/08/2026 After 15.00 PM

टीप:-

01. उपरोक्त कार्यों की निविदा की समान्य शर्तें धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति निविदा दस्तावेत व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https:cgeprocurement.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
02. विज्ञापन की प्रति httpd:cg.uad.gov.in में देखी जा सकती है ।

स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर पंचायत लखनपुर
जिला-सरगुजा,छ0ग0

नाम परिवर्तन सूचना

मैं संदीप कुमार सिंह आ0 कृष्ण देव सिंह,आयु लगभग 41 निवासी ग्राम कान्तीप्रकाशपुर,(बसोरपारा),तहसील अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा, छ0ग0। यह कि, मैं उपरोक्त पते का स्थायी निवासी हूं। मेरे पुत्र दिव्यांश सिंह का जन्म दिनांक- 15/10/2021 जिला अस्पताल अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 में हुआ है, मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में मेरी पत्नी का नाम तारा यादव (TARA YADAY) अंकित है,जो कि गलत है जिसे सुधार कर मेरी पत्नी का नाम सोना सिंह (Sona singh) करवाना चाहता हूं। जिसके लिये स्वं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि मेरी पत्नी सोना सिंह (Sona singh) के आधार कार्ड में सही नाम अंकित है। अतः आज से मेरे पत्नी के शासकीय,अर्धशाकीय एवं सभी दस्तावेज में सोना सिंह (Sona singh) पढ़ा एवं लिखा जावें।

शपथग्रहिता
संदीप कुमार सिंह

सूचना/सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं फूलमतिया / Fulmatiya पति श्री डहरू राम, ग्राम जामढोढी थाना सीतापुर, तहसील मैनापट, जिला सरगुजा, छ0ग0 की स्थायी निवासी हूँ। मेरे आधार संख्या 7024 0974 9643 में मेरा नाम फुलबसिया/ Fulbasiya गलत अंकित हो गया है, जबकि मेरे मतदाता परिचय पत्र एवं पेंशन प्रमाण पत्र में मेरा नाम फुलमतिया/Fulmatiya सही अंकित है। वर्तमान समय में उपरोक्त दोनो नामों की एक मात्र महिला मैं ही हूँ। मैं अपने आधार कार्ड संख्या 7024 0974 9643 में अपने नाम को वोटर कार्ड एवं पेंशन प्रमाण पत्र के अनसुार अंकित करवाना चाहती हूँ, जिस संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत की हूँ। मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में अंकित नाम फुलबसिया/ Fulbasiya के स्थान पर अपना नाम फुलमतिया/Fulmatiya दर्ज करवाना चाहती हूँ,अगर किसी को आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करावे ।

स्थान- अम्बिकापुर
दिनांक- 06.08.2026

भवदीय
फूलमलिया
मो0 नं0- 9009939072

कोसा की चमक अब वैश्विक बाजार तक...छत्तीसगढ़ का प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड 'कौशल फैब' लॉन्च

हथकरघा हमारी संस्कृति,रोजगार और आत्मनिर्भरता की सशक्त पहचान : सीएम साय

रायपुर,07 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन और स्वदेशी प्रदर्शनी में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने रेशम,हथकरघा,हस्तशिल्प,खादी एवं माटीकला बोर्ड के विभिन्न हितग्राहियों और मेधावी छात्र-छात्राओं को 10 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक की अनुदान एवं पुरस्कार राशि वितरित की। इस दौरान सीएम साय ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के नए प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड 'कौशल फैब'का शुभारंभ करते हुए उसके लोगो और कैटलॉग का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने हथकरघा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों, विशेषकर बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस दिवस को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का कोसा, बस्तर की बुनाई तथा प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा उत्पाद देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के हथकरघा उत्पादों को 'लोकल टू ग्लोबल' की नई पहचान दिलाना है। इसके लिए आधुनिक डिज़ाइन,कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, विपणन और नए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अंतर्गत किए गए अधिकांश वादों को राज्य सरकार ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि का भुगतान, भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण तथा तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना का पुनः संचालन सरकार की जनकल्याणकारी सोच का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामलला दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के 50 हजार से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्रीराम के दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी,जवाबदेह एवं भ्रष्टाचार-मुक्त शासन व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। ई-ऑफिस व्यवस्था,मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 तथा सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और घर बैठे शासकीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना तथा आत्मनिर्भर और समृद्ध छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है।

बुनकरों के लिए सुशासन सरकार की बड़ी पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों एवं शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 469 आवासविहीन बुनकर परिवारों के लिए बुनकर शेड सह आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में आयोजित 47 प्रदर्शनियों के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपये के हथकरघा उत्पादों की बिक्री हुई,जिससे बुनकरों को बेहतर बाजार उपलब्ध हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले ढाई वर्षों में 2,001 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई पारिश्रमिक के रूप में 68 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पाँच विक्रय भंडारों तथा केंद्रीय वस्त्रागार के माध्यम से विभिन्न शासकीय विभागों को 93 करोड़ रुपये के वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त बुनकरों द्वारा निर्मित 436 करोड़ रुपये के वस्त्रों की शासकीय खरीदी कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में देश के पाँच प्रमुख हवाई अड्डों पर छत्तीसगढ़ के हैंडलूम एवं हस्तशिल्प उत्पादों के शोरूम स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं,रायपुर में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल स्थानीय उत्पादों को आधुनिक विपणन मंच उपलब्ध कराएगा।

मुख्यमंत्री ने स्वदेशी प्रदर्शनी एवं स्टॉलों का अवलोकन किया,खरीदी कोसा साड़ी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ,बिलासा हैंडलूम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड,हस्तशिल्प विकास बोर्ड,सबरी एम्पोरियम तथा माटीकला बोर्ड सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाए गएस्टॉलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोसा,खादी, हस्तशिल्प,मृदाशिल्प एवं अन्य पारंपरिक उत्पादों का अवलोकन करते हुए कारीगरों से संवाद किया तथा उत्पादों की गुणवत्ता,विपणन और रोजगार की संभावनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों को अधिकाधिक अपनाने और प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने हथकरघा स्टॉल से स्वयं तत्काल भुगतान कर कोसा साड़ी खरीदी। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की खरीद ही बुनकरों और शिल्पकारों के श्रम एवं कौशल का सबसे बड़ा सम्मान है। मुख्यमंत्री के इस आत्मीय कदम से कार्यक्रम में उपस्थित बुनकरों और महिला कारीगरों का उत्साह दोगुना हो गया।

आत्मसमर्पित महिलाओं का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र

कार्यक्रम का सबसे प्रेरक और भावनात्मक क्षण वह रहा,जब बस्तर की आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने स्वदेशी फैशन शो में आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क एवं अन्य हैंडलूम परिधानों का आकर्षक प्रदर्शन किया। यह प्रस्तुति मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ती महिलाओं के आत्मविश्वास,सम्मानजनक पुनर्वास और बदलते बस्तर की सकारात्मक तस्वीर की सशक्त अभिव्यक्ति थी। उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित महिलाओं से आत्मीय संवाद किया,उनका उत्साह बढ़ाया और उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दीं। उल्लेखनीय है कि इनमें से लगभग सभी महिलाएँ पहली बार रायपुर पहुँची थीं।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किया बुनकरों का उत्साहवर्धन

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1 लाख 20 हजार परिवार हथकरघा एवं इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत किए जाने से इस क्षेत्र को नई पहचान और नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने सभी नागरिकों से प्रत्येक वर्ष कम से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने का आग्रह करते हुए कहा कि बुनकरों की मेहनत, उनकी कला और हमारी समृद्ध परंपरा को जीवित रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

ग्रामोद्योग मंत्री ने स्वदेशी आंदोलन की विरासत को किया याद

ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन ने देश में आत्मनिर्भरता की अलख जगाई थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ी का देशभर में विशिष्ट स्थान है और राज्य सरकार हथकरघा,हस्तशिल्प तथा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बुनकरों, शिल्पकारों और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके उत्पादों को व्यापक बाजार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एवं अन्य नवाचारों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ द्वारा एनआईसी के सहयोग से विकसित इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया। इस डिजिटल पहल से उत्पादों के भंडारण,प्रबंधन,विपणन तथा वितरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी,पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। इस अवसर पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकरों की डायरेक्टरी तथा टाई-डाई एवं बाँधनी रंगाई विषयक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। साथ ही जशपुर जिले के गोरिया में स्थापित होने वाली ग्लेजिंग यूनिट का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्रामोद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को अनुदान एवं पुरस्कार राशि वितरित की। उन्होंने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 935 छात्र-छात्राओं को 81.83 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। साथ ही 17 वरिष्ठ बुनकरों को सम्मान राशि देकर उनके उत्कृष्ट योगदान का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा संचालनालय के माध्यम से 49 बुनकरों के लिए बुनकर शेड सह आवास निर्माण हेतु 1.22 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त पाँच बुनकर सहकारी समितियों को भवन निर्माण के लिए 75 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई तथा 85 बुनकरों को उन्नत करघे एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए।

पेंशनरों को राहत : डीआर 55% से बढ़ाकर 58% किया

रायपुर,07 अगस्त 2026। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने अपने सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और वैज्ञानिकों को राहत देते हुए पेंशन पर मिलने वाले महंगाई राहत (डीआर) की दर 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सेवानिवृत्त प्राध्यापकों की ओर से चल रही हड़ताल के बीच लंबित पेंशन प्रकरणों की स्थिति भी स्पष्ट की है। प्रशासन के अनुसार,अब तक सेवानिवृत्त हुए 42 प्राध्यापकों और वैज्ञानिकों में से 15 को 90 प्रतिशत पेंशन की स्वीकृति देकर नियमित भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा 15 अन्य लंबित पेंशन मामलों को सत्यापन के लिए स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय भेजा गया है। वहां से मंजूरी मिलते ही संबंधित पेंशनरों को भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। वहीं, 12 अन्य प्रकरण अभी स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं और उन पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। विश्वविद्यालय ने बताया कि 90 प्रतिशत पेंशन पाने वाले कुछ मामलों में नियुक्ति आदेश की सेवा शर्तों और उनके पालन को लेकर लेखानियंत्रक तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय ने आपत्तियां दर्ज की हैं। इन मामलों को मार्गदर्शन के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। प्रशासन का कहना है कि विसंगतियां दूर होते ही संबंधित प्राध्यापकों और वैज्ञानिकों को तत्काल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि कार्यरत वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रस्ताव प्रबंध मंडल से पारित कर राज्य शासन को भेजा जा चुका है। इस पर शासन के मार्गदर्शन का अभी इंतजार है।

बिलासपुर में बच्ची के साथ रेप मोहल्ले का अंकल बना दरिंदा

बिलासपुर,07 अगस्त 2026। एक पांच साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक मोहल्ले में खेल रही बच्ची को साइकिल सिखाने के बहाने जंगल ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार सीपत थाना क्षेत्र की रहने वाली पांच साल की बच्ची बुधवार की सुबह अपने घर के पास मोहल्ले में खेल रही थी। उसी समय दीपक पटेल (30) वहां से गुजर रहा था। युवक ग्राम नीरतू का रहने वाला है। बच्ची को देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। उसने बच्ची को साइकिल सिखाने का झांसा दिया, जिसके बाद अपने साथ रेलहा जंगल की तरफ ले गया। इधर,दोपहर तक बच्ची घर नहीं पहुंची,तब परेशान परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान लोगों से पूछताछ में पता चला कि बच्ची को दीपक पटेल के साथ जाते देखा गया है। इससे घबराए परिजन बच्ची और दीपक को ढूंढते हुए जंगल तरफ गए। उन्होंने रास्ते में दीपक को पकड़ लिया। जब मां ने अपनी बच्ची से पूछताछ की,तब पता चला कि दीपक उसे साइकिल सिखाने के बहाने ले गया था। जिसके बाद जंगल में ले जाकर गंदा काम किया। यह सुनकर मां का दिल सहम गया। बच्ची की मां ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद आरोपी दीपक को ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में बच्ची की तरफ से उसकी मां ने थाने में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की भूपेश की मांग

चुनाव याचिका पर होगी सुनवाई,विजय बघेल ने दी थी विधायकी को चुनौती,आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

बिलासपुर,07 अगस्त 2026। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। हालांकि,कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बघेल चुनाव याचिका के ट्रायल के दौरान अपनी सभी कानूनी और तथ्यात्मक आपत्तियां उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। मामले में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बघेल की ओर से दायर चुनौती पर सुनवाई की। चुनाव याचिका भाजपा नेता और बघेल के चुनावी प्रतिद्वंद्वी विजय बघेल ने लगाया है। चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग से 48 घंटे पहले लागू साइलेंस पीरियड के दौरान भूपेश बघेल ने रोड शो किया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट में बघेल की ओर से दलील

बघेल की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि आरोप सही मान भी लिया जाए, तब भी यह केवल धारा 126 के

तहत चुनाव संबंधी अपराध हो सकता है,लेकिन इसे धारा 123 के तहत 'भ्रष्ट आचरण' नहीं माना जा सकता। सिब्बल ने कहा, 'धारा 126 एक चुनावी अपराध है। यह भ्रष्ट आचरण नहीं है। भ्रष्ट आचरण धारा 123 के तहत आता है।' उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कथित घटना का चुनाव परिणाम पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भूपेश बघेल ने लगभग 20 हजार मतों के अंतर से चुनाव जीता था। उन्होंने कहा कि कथित रोड शो में करीब 200 लोग थे और बघेल उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्हें जेड+ सुरक्षा मिली थी। हालांकि, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि कथित उल्लंघन से चुनाव परिणाम वास्तव में प्रभावित हुआ या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है, जिसका निर्धारण सबूतों के आधार पर किया जाना आवश्यक है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जब आरोप भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में ही नहीं आता तो बघेल को पूरी चुनावी सुनवाई से गुजरने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इस पर न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि 'आपके पास बचाव के लिए एक तर्कसंगत मामला है।' सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए बघेल की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी कि वे चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान अपने सभी कानूनी और तथ्यात्मक तर्क हाईकोर्ट के समक्ष उठा सकते हैं।

विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी को दी चुनौती

दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी खत्म करने के लिए चुनाव याचिका लगाई है। 2024 में दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग से ठीक पहले प्रचार बंद होने की अवधि में भूपेश बघेल ने अपने समर्थकों के साथ पाटन क्षेत्र में रैली और रोड शो किया था। इस दौरान उन्होंने चुनावी नारे लगवाए और वोट मांगकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 का सीधा उल्लंघन किया, जिसका वीडियो भी बनाया गया था।

सीजीएमएससी में रिएजेंट घोटाला...

मोक्षित-कार्पोरेशन के डायरेक्टर को राहत नहीं,161 करोड़ के रिएजेंट बर्बाद

बिलासपुर,07 अगस्त 2026। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने हमर लैब योजना में मेडिकल उपकरण और रिएजेंट खरीदी घोटाले के आरोपी मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को राहत देने से इनकार कर दिया। डिवीजन बेंच ने एफआईआर,चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामला केवल अनुबंध या भुगतान विवाद का नहीं, बल्कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में साजिश, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोपों से जुड़ा है। ऐसे मामलों में सबूतों का परीक्षण ट्रायल कोर्ट में ही होगा। सीजीएमएससी ने वर्ष 2022 में हमर लैब योजना के लिए दवाओं की खरीदी के लिए टेंडर जारी किया था। इस मामले में करोड़ों की गड़बड़ी का आरोप लगा। मामले की जांच हुई। जांच एजेंसी का आरोप है कि टेंडर की शर्तें इस तरह बनाई गईं कि मोक्षित कॉर्पोरेशन को फायदा मिले। इसके बाद जरूरत और उपलब्ध अधोसंरचना का आकलन किए बिना करीब 314 करोड़ रुपए के रिएजेंट खरीदे गए। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर, यूपीएस और अन्य आवश्यक सुविधाएं नहीं होने से करीब 161 करोड़ रुपए के रिएजेंट इस्तेमाल से पहले ही एक्सपायर हो गए,जिससे शासन को भारी नुकसान हुआ। मोक्षित कार्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कहा कि पूरा विवाद अनुबंध और भुगतान से जुड़ा है। कंपनी ने तय सप्लाई कर दी है, लेकिन उसके लगभग 338 करोड़ रुपए अभी भी सीजीएमएससी पर बकाया हैं। साथ ही कंपनी ने जीएसटी और आयकर के रूप में बड़ी राशि जमा की है, इसलिए उसे गलत आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप निराधार है। यह भी कहा गया कि कंपनी ने समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग और सीजीएमएससी को अधोसंरचना की कमी और रिएजेंट खराब होने की आशंका जताई थी।

वक्फ-बोर्ड की जमीन का 1.60 करोड़ में सौदा

बिलासपुर में दान में दी गई थी जमीन,7 लाख एडवांस नहीं लौटाने पर धोखाधड़ी का केस

बिलासपुर,07 अगस्त 2026। बिलासपुर में 56 साल पहले वक्फ बोर्ड को दान की जा चुकी जमीन का 1.60 करोड़ रुपए में सौदा कर 7 लाख रुपए एडवांस लेने का मामला सामने आया है। बाद में नजूल रिकॉर्ड की जांच में जिस जमीन को 3120 वर्गफुट बताकर बेचा जा रहा था, उसका वास्तविक रकबा सिर्फ 430 वर्गफुट निकला। इस मामले की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक,खपरगंज के रहने वाले नबी बख्श और मोहम्मद कासिम ने कश्यप कॉलोनी की रहने वाली संजना वर्मा से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि खपरगंज नजूल शीट नंबर-33 के प्लॉट नंबर 1/1 और 1/2 में उनकी दादी बसारत बी के नाम 3120 वर्गफुट जमीन पर खपरैलनुमा मकान दर्ज है। दोनों ने संजना को भरोसा दिलाया कि नामांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के छह महीने बाद जमीन की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। इसके बाद जमीन का सौदा 1.60 करोड़ रुपए में तय हुआ। 18 अक्टूबर 2024 को दोनों पक्षों के बीच नोटरी पर इकरारनामा हुआ।

भिलाई ट्रिपल मर्डर केस में फांसी रद्द...आखिरी सांस तक जेल : पत्नी-डेढ़ माह की बेटी समेत तीन की हत्या,हाईकोर्ट बोला...मामला रेयरेस्ट नहीं

बिलासपुर,07 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भिलाई के तालपुरी में हुए चर्चित ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य आरोपी रवि शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उसकी सजा बरकरार रखते हुए ट्रायल कोर्ट की फांसी की सजा को बदलकर बिना किसी छूट के उम्रकैद कर दिया है। यानी अब आरोपी रवि शर्मा को मरते दम तक जेल में रहना होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की श्रेणी में नहीं आता,इसलिए फांसी की सजा देना जरूरी नहीं है। बता दें कि निचली अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। 21 जनवरी 2020 को तालपुरी के एक किराये के मकान में रवि शर्मा की पत्नी मंजू शर्मा,उनकी डेढ़ माह की बेटी और एन. राजू के शव मिले थे। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए तीनों के शवों को जलाने की कोशिश की थी। जांच के

दौरान पुलिस को आरोपी के पास से मिला चिपकने वाला टेप घटनास्थल पर इस्तेमाल किए गए टेप से मेल खा गया। उसके पास से नींद की दवा एल्प्रेक्स 0.5 का खाली रैपर भी मिला। वहीं, दीवार पर लिखे गए नोट की लिखावट भी आरोपी की लिखावट से मिल गई। आरोपी रवि शर्मा ने बेहद चालाकी से हत्या की पूरी योजना बनाई थी। खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए उसने अनजान व्यक्ति एन. राजू की हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए तीनों शवों को गैस सिलेंडर से जलाने की कोशिश की। वारदात से पहले उसने पत्नी, अपनी डेढ़ माह की बेटी और एन. राजू को नींद की दवा एल्प्रेक्स 0.5 खिलाई। फिर उनके मुंह, हाथ और पैर पर टेप बांध दिया,जिससे दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। बाद में आरोपी ने दीवार पर एक नोट लिखा, ताकि लोगों को लगे कि उसने पत्नी की बेवफाई से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन मृतका की मां को आए एक अनजान फोन कॉल से मामले का खुलासा हुआ। जांच के दौरान आरोपी के पास से मिला चिपकने वाला टेप,मृतकों के मुंह और हाथ-पैर पर लगा टेप फोरेंसिक जांच में एक ही पाया गया। इसके अलावा आरोपी के पास से नींद की दवा एल्प्रेक्स 0.5 का खाली रैपर भी बरामद हुआ।

छत्तीसगढ़ में पहली बार मिलेगा 10 किलो वाला सिलेंडर,ऑनलाइन बुकिंग के 4 घंटे में पहुंचेगा घर

रायपुर,07 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है। 15 अगस्त से रायपुर में पहली बार 10 किलो का हल्का और पारदर्शी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इस सिलेंडर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पेट्रोलियम कंपनियों के मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन बुक किया जा सकेगा और बुकिंग के करीब चार घंटे के भीतर इसकी होम डिलीवरी की जाएगी। शुरुआती चरण में यह सेवा रायपुर में शुरू होगी, जिसके बाद इसे पूरे प्रदेश में

विस्तार दिया जाएगा। नया 10 किलो एलपीजी सिलेंडर पारंपरिक लोहे के सिलेंडरों की तुलना में काफी हल्का होगा। यह फाइबर ग्लास और पॉलीमर सामग्री से तैयार किया गया है, जिससे इसे उठाना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होगा। इसकी पारदर्शी बॉडी के कारण उपभोक्ता बिना किसी उपकरण के यह देख सकेंगे कि सिलेंडर में कितनी गैस शेष है। कंपनी का दावा है कि इसकी बनावट अधिक सुरक्षित है और जंग लगने की समस्या भी नहीं होगी। इस नए कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को लगभग 3,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा कराने होंगे। इसके अलावा रेगुलेटर के लिए करीब 250 रुपये अलग से देने होंगे। यह सिक्योरिटी राशि कनेक्शन बंद कराने पर वापस कर दी जाएगी। रायपुर में एक बार गैस रिफिल कराने की अनुमानित कीमत 715 से 730 रुपये के बीच रहेगी। यह सुविधा केवल नए उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगी। जिन लोगों के पास पहले से घरेलू गैस कनेक्शन है, वे भी निर्धारित सिक्योरिटी राशि जमा कर नया 10 किलो सिलेंडर ले सकेंगे। कनेक्शन लेने के लिए आधार कार्ड, आवेदन फॉर्म और आवश्यक घोषणा पत्र जमा करना होगा। यह सिलेंडर खासतौर पर छोटे परिवारों, अकेले रहने वाले लोगों, यात्रा या पिकनिक पर जाने वालों और आपातकालीन उपयोग के लिए उपयोगी माना जा रहा है।

उपभोक्ता संबंधित पेट्रोलियम कंपनियों के मोबाइल एप डाउनलोड कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर नजदीकी गैस एजेंसी से भी कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। कंपनियों का कहना है कि समयबद्ध डिलीवरी और हल्के सिलेंडर की सुविधा से उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)